RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 196
दि. 20.04.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

श्रीनगर एयरपोर्ट पर सैटेलाइट फोन के साथ पकड़े गए अमेरिकी नागरिक: सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, जांच के घेरे में कई अहम पहलू

श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक नियमित सुरक्षा जांच उस समय गंभीर मामले में बदल गई, जब दो अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में ले लिया गया। उनके सामान की तलाशी के दौरान एक प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन/ट्रैकर बरामद हुआ, जिसने सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत सतर्क कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक, हिरासत में लिए गए व्यक्तियों में से एक की पहचान जेफरी स्कॉट प्रैथर के रूप में हुई है, जबकि दूसरे व्यक्ति की पहचान फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है, जब जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर पहले से ही अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। सैटेलाइट फोन जैसे उपकरण सामान्य मोबाइल नेटवर्क से अलग काम करते हैं और इनका सिग्नल पारंपरिक निगरानी प्रणाली से आसानी से पकड़ में नहीं आता। यही कारण है कि ऐसे डिवाइस सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन जाते हैं।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बरामद डिवाइस एक उन्नत सैटेलाइट कम्युनिकेशन उपकरण है, जिसे बिना अनुमति भारत में रखना कानूनन प्रतिबंधित है। ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल आमतौर पर उन क्षेत्रों में किया जाता है, जहां मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं होता, लेकिन संवेदनशील इलाकों में इनका दुरुपयोग अवैध संचार या संदिग्ध गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है। घटना के तुरंत बाद दोनों विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब उनसे पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनके पास यह डिवाइस किस उद्देश्य से था

और क्या उन्होंने इसके लिए भारत सरकार से आवश्यक अनुमति ली थी या नहीं। भारत में सैटेलाइट फोन या किसी भी प्रकार के स्वतंत्र संचार उपकरण के उपयोग के लिए दूरसंचार विभाग से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होता है। बिना अनुमति ऐसे उपकरण का रखना या उपयोग करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। एयरपोर्ट सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत जैसे ही ऐसे उपकरण का पता चलता है, तुरंत कार्रवाई की जाती है और संबंधित व्यक्ति को पूछताछ के लिए रोका जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा से सटे और संवेदनशील क्षेत्रों में इस तरह के उपकरणों की मौजूदगी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह केवल तकनीकी मामला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा भी है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां हर छोटे से छोटे पहलू की गहन जांच कर रही हैं—चाहे वह डिवाइस का स्रोत हो, उसके इस्तेमाल का उद्देश्य हो या फिर उससे जुड़े संभावित संपर्क। यह पहली बार नहीं है जब भारत में इस तरह की घटना सामने आई हो। इससे पहले भी कई विदेशी नागरिकों को सैटेलाइट फोन रखने के आरोप में हिरासत में लिया जा चुका है। पिछले वर्ष पुडुचेरी एयरपोर्ट पर एक अमेरिकी डॉक्टर के पास से इरीडियम सैटेलाइट फोन बरामद हुआ था। इसके अलावा एक चीनी नागरिक और एक ब्रिटिश अधिकारी को भी इसी तरह के मामलों में पकड़ा गया था। इन घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों को और अधिक सतर्क कर दिया है। इस ताजा मामले में भी जांच कई स्तरों पर की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या यह केवल नियमों की अनदेखी का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क या उद्देश्य छिपा हुआ है। साथ ही यह भी जांचा जा रहा है कि क्या इन दोनों व्यक्तियों का किसी संदिग्ध संगठन या गतिविधि से कोई संबंध है। घटना के बाद एयरपोर्ट और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा जांच को और सख्त किए जाने की संभावना जताई जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ-साथ सुरक्षा चुनौतियां भी जटिल होती जा रही हैं, इसलिए सतर्कता और सख्ती दोनों जरूरी हैं।

श्रीनगर एयरपोर्ट पर हुई यह घटना केवल एक कानूनी उल्लंघन का मामला नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत भी है कि सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे को लेकर कितनी सजग हैं। आने वाले दिनों में जांच से और तथ्य सामने आ सकते हैं, जो इस पूरे मामले की दिशा तय करेंगे। फिलहाल, दोनों विदेशी नागरिकों से पूछताछ जारी है और एजेंसियां हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न हो।

ओडिशा बना सेमीकंडक्टर हब की ओर अग्रसर: देश की पहली 3D पैकेजिंग यूनिट से हाई-टेक क्रांति की शुरुआत

भुवनेश्वर की इन्फो वैली में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर एक ऐसी परियोजना की नींव रखी गई, जो भारत के तकनीकी भविष्य को नई दिशा देने की क्षमता रखती है। देश की पहली एडवांस्ड 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट का शिलान्यास केवल एक औद्योगिक पहल नहीं, बल्कि भारत के 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इस परियोजना का उद्घाटन अश्विनी वैष्णव ने किया, जिन्होंने इसे भारत के हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 'गेम चेंजर' बताया। उनके अनुसार, यह यूनिट न केवल देश की तकनीकी क्षमता को बढ़ाएगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को भी मजबूत करेगी।

इस प्लांट की सबसे खास बात है इसमें इस्तेमाल होने वाली अत्याधुनिक 3D ग्लास सबस्ट्रेट तकनीक। अब तक सेमीकंडक्टर निर्माण में मुख्य रूप से सिलिकॉन सबस्ट्रेट का उपयोग होता रहा है, लेकिन यह नई तकनीक चिप्स को अधिक तेज, अधिक कुशल और अधिक सक्षम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 3D पैकेजिंग तकनीक के जरिए चिप्स को बहु-स्तरीय संरचना में तैयार किया जाता है, जिससे उनकी प्रोसेसिंग क्षमता कई गुना बढ़ जाती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस यूनिट का प्रभाव केवल एक उद्योग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि

यह कई उभरते क्षेत्रों को सीधे प्रभावित करेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 5G नेटवर्क, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा तकनीक जैसे क्षेत्रों में इस नई तकनीक से क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हाई-परफॉर्मेंस चिप्स की मांग लगातार बढ़ रही है और यह यूनिट उस मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इस परियोजना में लगभग 2,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है, जो इसे देश की प्रमुख हाई-टेक परियोजनाओं में शामिल करता है। मोहन चरण माझी ने इसे ओडिशा और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह निवेश राज्य को एक नए औद्योगिक युग में प्रवेश दिलाएगा। पहले चरण में इस यूनिट से बड़े पैमाने पर उत्पादन की योजना बनाई गई है। अनुमान है कि हर साल लगभग 70,000 ग्लास पैनल, 50 मिलियन असेंबल्ड यूनिट और 13,000 एडवांस्ड 3DHI मॉड्यूल तैयार किए जाएंगे। यह उत्पादन क्षमता न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाएगी।

रोजगार के लिहाज से भी यह परियोजना बेहद महत्वपूर्ण है। शुरुआती चरण में ही 2,500 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से इससे हजारों अन्य रोजगार अवसर भी पैदा होंगे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और युवाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे।

इस परियोजना में वैश्विक कंपनियों की दिलचस्पी भी इसे और खास बनाती है। Intel, Lockheed Martin और Applied Materials जैसी दिग्गज कंपनियों की भागीदारी और रुचि इस बात का संकेत है कि ओडिशा तेजी से एक उभरते हुए ग्लोबल हाई-टेक हब के रूप में सामने आ रहा है।

इंटेल के सीईओ लिप-बू टैन ने भी ओडिशा की संभावनाओं की सराहना करते हुए कहा कि यहां उपलब्ध मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर—जैसे पर्याप्त बिजली, भरोसेमंद जल संसाधन और कुशल मानव संसाधन—इस तरह की उन्नत मैन्युफैक्चरिंग के लिए आदर्श वातावरण तैयार करते हैं। सरकार की योजना केवल इस यूनिट की स्थापना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके विस्तार की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। पहले चरण के सफल होने के बाद इसकी उत्पादन क्षमता को दोगुना करने की योजना बनाई गई है। साथ ही राज्य में रेलवे, शहरी विकास और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी परियोजनाओं पर भी तेजी से काम किया जा रहा है, ताकि उद्योगों को बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाएं मिल सकें। भारत लंबे समय से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रयास कर रहा है। वैश्विक स्तर पर चिप्स की कमी और सप्लाई चेन में व्यवधान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। ऐसे में यह परियोजना न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भी बेहद अहम है। भुवनेश्वर में शुरू हुई यह पहल भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। यह न केवल देश को हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ाएगी, बल्कि वैश्विक तकनीकी मानचित्र पर भारत की स्थिति को भी मजबूत करेगी।

समुद्र किनारे बसी बस्ती राख में बदली: सैंडाकन में भीषण आग से 1,000 घर तबाह, 9,000 से ज्यादा लोग बेघर

सैंडाकन के बाटू सापी इलाके की एक शांत रात रविवार तड़के अचानक भयावह त्रासदी में बदल गई, जब कम्पुंग बहागिया बस्ती में लगी भीषण आग ने देखते ही देखते पूरी आबादी को अपनी चपेट में ले लिया। सुबह करीब 1:30 बजे शुरू हुई इस आग ने कुछ ही घंटों में ऐसा विकराल रूप ले लिया कि करीब 1,000 घर जलकर खाक हो गए और 9,000 से अधिक लोग बेघर हो गए। यह हादसा मलेशिया के इतिहास में शहरी बस्तियों में लगी सबसे विनाशकारी आग की घटनाओं में से एक माना जा रहा है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस भीषण तबाही के बावजूद किसी की जान नहीं गई, लेकिन कई लोग अपने सामान को बचाने और दूसरों की मदद करने के दौरान हल्के रूप से घायल हो गए।

इस आग के इतनी तेजी से फैलने के पीछे बस्ती की संरचना एक बड़ा कारण रही। कम्पुंग बहागिया समुद्र किनारे बसी एक घनी आबादी वाली बस्ती है, जहां अधिकांश घर लकड़ी के खंभों पर बने होते हैं और एक-दूसरे के बेहद करीब स्थित होते हैं। जैसे ही आग लगी, तेज हवाओं और ज्वलनशील सामग्री ने उसे कुछ ही मिनटों में कई घरों तक पहुंचा दिया। लोगों को अपने घर छोड़ने का बहुत कम समय मिला और कई परिवारों को अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी वहीं छोड़कर भागना पड़ा।

घटना के दौरान सबसे बड़ी चुनौती दमकल

विभाग के सामने पहुंच और संसाधनों की रही। संकरी गलियों के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सीधे घटनास्थल तक नहीं पहुंच सकीं। इसके अलावा, समुद्र में पानी का स्तर कम होने की वजह से आग बुझाने के लिए पर्याप्त पानी जुटाना भी मुश्किल हो गया।

करीब 35 दमकलकर्मी सैंडाकन और किनाबाटांगन से मौके पर पहुंचे और उन्होंने पानी के टैंकरों तथा पास की एक फैक्ट्री के हाइड्रेंट का सहारा लेकर आग बुझाने का प्रयास किया। तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह करीब 4 बजे आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक बस्ती का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो चुका था।

पुलिस के अनुसार, इस इलाके में कुल लगभग 1,200 घर थे, जिनमें से करीब 1,000 घर आग की चपेट में आ गए। केवल 200 घर ही इस भीषण तबाही से बच पाए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पूरे इलाके को 'डिजास्टर एरिया' घोषित कर दिया है।

हजारों बेघर हुए लोगों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सिर छुपाने की है। प्रशासन ने तत्काल राहत कार्य शुरू करते हुए तीन अस्थायी राहत केंद्र स्थापित किए हैं—पीपीआर सैंडाकन, पीपीआर बाटू सापी हॉल और एसके कम्पुंग गैस स्कूल। इन केंद्रों में प्रभावित लोगों का पंजीकरण किया जा रहा है और उन्हें भोजन, पानी, कपड़े तथा अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

हालांकि, राहत कार्यों के सामने भी कई व्यावहारिक चुनौतियां हैं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास राहत केंद्रों तक पहुंचने के लिए साधन नहीं हैं। ऐसे लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए अलग से इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि कोई भी पीड़ित सहायता से वंचित न रह जाए।

इस हादसे ने हजारों परिवारों को एक झटके में बेघर कर दिया है। जिन घरों में कभी जिंदगी की हलचल थी, वे अब राख के ढेर में बदल चुके हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर कोई इस त्रासदी से मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग और अन्य जांच एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि आग कैसे लगी और क्या इसमें किसी प्रकार की लापरवाही या तकनीकी कारण शामिल था। प्रारंभिक जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन ने पीड़ितों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें जल्द से जल्द राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार और विभिन्न एजेंसियां मिलकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं कि प्रभावित लोगों को रहने के लिए सुरक्षित स्थान और जीवन की आवश्यक सुविधाएं मिल सकें। यह हादसा केवल एक प्राकृतिक या आकस्मिक आपदा नहीं, बल्कि यह शहरी योजना, बुनियादी ढांचे और आपदा प्रबंधन की चुनौतियों को भी उजागर करता है। समुद्र किनारे बसे ऐसे घनी आबादी वाले इलाकों में आग जैसी घटनाएं हमेशा बड़ा खतरा बनी रहती हैं, और यह घटना एक बार फिर इस खतरे की गंभीरता को सामने लेकर आई है।

सैंडाकन आज एक गहरे सदमे से गुजर रहा है। हजारों लोग खुले आसमान के नीचे हैं, लेकिन राहत की एक छोटी सी उम्मीद भी है—कि जल्द ही वे फिर से अपने जीवन को पटरी पर ला सकेंगे। फिलहाल, पूरा ध्यान राहत और पुनर्वास पर केंद्रित है, ताकि इस त्रासदी से उबरने की प्रक्रिया शुरू हो सके।

इस्लामाबाद में 'हाई अलर्ट' कूटनीति: ट्रंप के संभावित दौरे की अटकलों के बीच सड़कों पर सन्नाटा, रेड जोन सील

इस्लामाबाद में रविवार को अचानक बदले हालात ने पूरे शहर की रफ्तार थाम दी। राजधानी की प्रमुख सड़कों पर बैरिकेड्स, सुरक्षा बलों की भारी तैनाती और रेड जोन का पूर्ण सील—इन सबने मिलकर ऐसा माहौल बना दिया, मानो शहर किसी बड़े घटनाक्रम की तैयारी में 'लॉकडाउन' की स्थिति में हो।

इस असाधारण सुरक्षा व्यवस्था के पीछे कूटनीतिक हलचल को मुख्य वजह माना जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित दूसरे दौर की शांति वार्ता की अटकलों ने इस पूरे घटनाक्रम को और भी अहम बना दिया है। हालांकि अब तक किसी भी देश—चाहे वह पाकिस्तान हो, अमेरिका हो या ईरान—की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो तैयारियां दिख रही हैं, वे किसी बड़े कूटनीतिक आयोजन की ओर साफ इशारा कर रही हैं।

सूत्रों के अनुसार, एक हाई-लेवल अमेरिकी डेलिगेशन की एडवांस सुरक्षा टीम पहले ही इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। इसके साथ ही यह भी चर्चा है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद भी पाकिस्तान आ सकते हैं, लेकिन यह दौरा तभी संभव होगा जब अमेरिका और ईरान के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर की स्थिति बने। इस बयान को रणनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, जो बताता है कि वार्ता अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ सकती है।

हाल के दिनों में अमेरिकी प्रतिनिधियों की आवाजाही ने इन अटकलों को और बल दिया है। 11 अप्रैल को जेडी वेंस

लगभग 17 घंटे की लंबी उड़ान के बाद इस्लामाबाद पहुंचे थे। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक, दो अमेरिकी कार्गो विमान नूर खान एयरबेस पर उतरे हैं, जिससे संकेत मिलता है कि कोई बड़ा प्रतिनिधिमंडल या लॉजिस्टिक तैयारी चल रही है।

सुरक्षा व्यवस्था के तहत इस्लामाबाद के रेड जोन और एक्सटेंडेड रेड जोन को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। आम नागरिकों की आवाजाही पर कड़ी पाबंदी लगाई गई है और लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी जा रही है। शहर की प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है, जिससे दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

सिर्फ इस्लामाबाद ही नहीं, बल्कि पास के रावलपिंडी में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहां सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर अस्थायी रोक लगा दी गई, हालांकि बाद में निजी वाहनों को सीमित छूट दी गई। प्रशासन ने भारी वाहनों और बसों के संचालन को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया है, जिससे आम लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू राजधानी के प्रमुख होटलों में देखने को मिला है। सेरेना होटल इस्लामाबाद और मैरियट होटल इस्लामाबाद ने नई बुकिंग लेना बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, पहले से ठहरे मेहमानों को भी अन्य स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। यह संकेत देता है कि इन होटलों को संभावित कूटनीतिक बैठकों के लिए सुरक्षित और विशेष रूप से तैयार किया जा रहा है।

पिछले घटनाक्रम पर नजर डालें तो अमेरिका और ईरान के बीच पहला दौर 12 अप्रैल को समाप्त हुआ था, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान इस पूरी प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और लगातार दोनों पक्षों के संपर्क में है।

हालांकि ईरान की ओर से यह संकेत भी मिला है कि वह प्रत्यक्ष वार्ता को अधिक प्रभावी मानता है और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से कई बार भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके बावजूद इस्लामाबाद को वार्ता स्थल के रूप में चुना जाना यह दर्शाता है कि क्षेत्रीय कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका इस समय कितनी महत्वपूर्ण हो गई है।

सूत्रों के मुताबिक, दूसरे दौर की वार्ता की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन यह बैठक जल्द—संभवतः अगले कुछ दिनों में—हो सकती है। ऐसे में राजधानी में बढ़ी सुरक्षा, सड़कों का बंद होना, होटलों की बुकिंग रोकना और विदेशी विमानों की आवाजाही—ये सभी संकेत मिलकर एक बड़े कूटनीतिक घटनाक्रम की ओर इशारा कर रहे हैं।

विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह वार्ता सफल होती है, तो न केवल मध्य-पूर्व में तनाव कम हो सकता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। वहीं, अगर बातचीत विफल होती है, तो हालात और बिगड़ सकते हैं, जिसका असर तेल बाजार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ेगा।

फिलहाल, इस्लामाबाद एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां हर गतिविधि, हर सुरक्षा कदम और हर कूटनीतिक संकेत को बेहद ध्यान से देखा जा रहा है। शहर की सड़कों पर पसरा सन्नाटा इस बात का संकेत है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा होने वाला है—अब बस इंतजार है उस आधिकारिक घोषणा का, जो इन अटकलों को हकीकत में बदल सकती है।

संपादकीय

अमेरिकी सियासत में 'पनौती' का नया किस्सा: जेडी वैंस पर उठते सवाल

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप, व्यंग्य और छवि-निर्माण का खेल हमेशा से चलता रहा है, लेकिन कभी-कभी यह खेल इतना दिलचस्प मोड़ ले लेता है कि वह किसी एक व्यक्ति की पहचान तक बदल देता है। इन दिनों अमेरिका की राजनीति में कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है, जहां जेडी वैंस को लेकर एक अजीब सा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। यह नैरेटिव उन्हें एक 'पनौती' के रूप में पेश करता है—एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मौजूदगी किसी भी घटना को नकारात्मक दिशा में मोड़ देती है।

यह कहानी केवल एक व्यक्ति की आलोचना नहीं है, बल्कि यह आधुनिक मीडिया, मीम संस्कृति और राजनीतिक प्रचार के उस ताने-बाने को भी उजागर करती है, जिसमें किसी भी नेता की छवि को कुछ ही दिनों में बना या बिगाड़ा जा सकता है। अमेरिका जैसे विकसित लोकतंत्र में भी इस तरह की धारणा बनना यह दर्शाता है कि राजनीति में भावनाओं और धारणाओं की भूमिका कितनी गहरी हो चुकी है।

दरअसल, हाल के घटनाक्रमों ने जेडी वैंस को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। कहा जा रहा है कि जहां-जहां वे गए, वहां कुछ न कुछ उल्टा ही हो गया। उदाहरण के तौर पर, जब वे धार्मिक मुलाकात के लिए गए तो वहां अप्रत्याशित घटनाएं सामने आ गईं। इसी तरह, जब वे विक्टर ऑर्बान के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे, तो नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। इन घटनाओं को जोड़कर एक ऐसी कथा बनाई जा रही है, जिसमें वैंस को 'अपशकुन' के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह केवल संयोग है या फिर इसे जानबूझकर एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है? राजनीति में विरोधियों को कमजोर करने के लिए इस तरह की छवि बनाना कोई नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि नेताओं को कभी 'तानाशाह', कभी 'कमजोर' और कभी 'अभागा' तक कहा गया है। लेकिन 'पनौती' जैसा शब्द, जो आमतौर पर भारतीय सामाजिक संदर्भ में ज्यादा प्रचलित है, उसका अमेरिकी राजनीति में इस्तेमाल होना अपने आप में दिलचस्प है।

इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाता है। ट्रंप, जो अपनी स्पष्टवादिता और आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कई बार वैंस को अपना करीबी बताया है। ऐसे में जब वैंस को लेकर नकारात्मक नैरेटिव बनता है, तो उसका असर कहीं न कहीं ट्रंप की छवि पर भी पड़ता है। हालांकि, ट्रंप जैसे नेता के लिए यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वे पहले भी कई विवादों का सामना कर चुके हैं और हर बार अपनी शैली में जवाब देते रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले में मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका बेहद अहम रही है। आज के दौर में किसी भी घटना का विश्लेषण केवल तथ्यों के आधार पर नहीं होता, बल्कि उसमें व्यंग्य, मीम्स और जनभावनाओं का भी बड़ा योगदान होता है। ट्विटर, फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म पर वैंस को लेकर जो मजाक और टिप्पणियां की जा रही हैं, वे इस बात का प्रमाण हैं कि कैसे डिजिटल युग में छवि निर्माण एक सामूहिक प्रक्रिया बन चुकी है। लेकिन क्या किसी नेता को 'पनौती' कहना उचित है? यह सवाल केवल नैतिकता का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का भी है। एक लोकतंत्र में नेताओं का मूल्यांकन उनके काम, नीतियों और निर्णयों के आधार पर होना चाहिए, न कि अंधविश्वास या संयोगों के आधार पर। अगर किसी नेता के साथ कुछ घटनाएं नकारात्मक रूप से जुड़ जाती हैं, तो उसका विश्लेषण तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर होना चाहिए, न कि उसे अंधविश्वास का रूप देकर।

इस पूरे प्रकरण में एक सांस्कृतिक पहलू भी छिपा हुआ है। 'पनौती' जैसा शब्द भारतीय समाज में गहराई से जुड़ा हुआ है, जहां इसे अक्सर किसी दुर्भाग्य का कारण माना जाता है। लेकिन जब यही अवधारणा अमेरिकी राजनीति में प्रवेश करती है, तो यह एक तरह का सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी दिखाती है—हालांकि यह आदान-प्रदान सकारात्मक कम और व्यंग्यात्मक ज्यादा है। अंततः, यह कहना गलत नहीं होगा कि जेडी वैंस के इर्द-गिर्द बना यह 'पनौती' वाला नैरेटिव राजनीति के उस बदलते स्वरूप को दर्शाता है, जहां तथ्यों से ज्यादा धारणाएं मायने रखती हैं। यह हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं, जहां नेताओं का मूल्यांकन उनके कार्यों से ज्यादा उनके 'भाग्य' के आधार पर किया जाएगा।

उगते सागर ने बचपन छीन बढ़ाये बाल विवाह

> "सुंदरबन जैसे इलाके में बड़ी संख्या में किशोरियों की शादी मात्र 'परंपरा' नहीं। यह कमजोर आर्थिक हालत में जीवन-रक्षा की रणनीति है। समुद्र में बार-बार चक्रवात आने, तटबंध टूटने, खारी मिट्टी से कृषि व मछली पालन प्रभावित होता है, जिससे आजीविका पर संकट आने से बाल-विवाह बढ़ते हैं।

सुंदरबन इलाके में जब सागर की लहरें धीरे-धीरे दलदली मिट्टी पर आती हैं- नमक और तूफान की तीव्रता से बंधा तट कांपता है, वहां बचपन की मासूमियत भी खतरे में पड़ जाती है। यहां गांवों में, घर की दीवारें धंसती मिट्टी पर टिकी हैं। इस संकट में सबसे अधिक प्रभावित होती हैं लड़कियां, जिनकी उम्र के सबसे खूबसूरत पल यानी खेल, पढ़ाई और बचपन की जिज्ञासाओं से लबालब होते हैं। वे सब जलवायु आपदाओं, गरीबी और सामाजिक असमानताओं के दबाव में जल्दी ही विवाह की आग में झोंक दी जाती हैं।

गोसाबा द्वीप की गलियों में एक 14 वर्षीय लड़की, अजूं बागदीस, सुबह के अंधेरे में अपने छोटे-छोटे पैरों से खारे पानी में छलकते पानी को चीरते हुए भागती है, अपने साथ केवल कुछ कपड़ों का बंडल लिए हुए। सूरज की पहली किरणों से पहले ही वह अपनी जीवन यात्रा में उस मोड़ पर पहुंच चुकी होगी, जहां उसके बचपन को हमेशा के लिए त्याग दिया जाएगा। विवाह की रस्में साधारण होती हैं—कोई भव्य दावत नहीं, बस कुछ रिश्तेदार, उधार ली गई साड़ी और एक जीवन जिसे आज़ाद महसूस करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। यह जलवायु संकट की अदृश्य कीमत है, जिसे समाज और व्यवस्था ने लड़कियों की मासूमियत के रूप में वसूल लिया। हालिया सर्वेक्षण इस संकट की गंभीरता को उजागर करते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–5 में पाया गया कि पश्चिम बंगाल में 20–24 वर्ष की उम्र की लगभग 42 प्रतिशत महिलाएं 18 वर्ष की उम्र से पहले ही विवाहिता हो चुकी थीं, जो राष्ट्रीय औसत 23.3 प्रतिशत का लगभग दोगुना है। सुंदरबन के द्वीपों में, गोसाबा ब्लॉक खासकर बाल विवाह के लिए चिन्हित है, जहां किशोरियों को घर का बोझ घटाने को विवाह करने को मजबूर किया जाता है। यहां के ग्रामीण रात में किए जाने वाले विवाहों की कहानियां फुसफुसाते हैं, जो

अक्सर बिना पंजीकरण, अधिकारी की नज़र से दूर, अनदेखी रह जाती हैं। यूनिसेफ के अनुमान के अनुसार, भारत के बाल विवाहों में पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी 13-15 प्रतिशत है, और इस डेल्टा के द्वीप-गोसाबा से लेकर बसंती, काकद्वीप और नामखाना तक—हर साल सैकड़ों किशोरियों को विवाह के बंधन में बांधते हैं।

सरकारी हस्तक्षेप मौजूद हैं, लेकिन वे सतह तक ही सीमित हैं। साल 2023 में अधिकारियों ने दावा किया कि 1,500 बाल विवाहों को रोका गया और लगभग 900 एफआईआर दर्ज की गईं, लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि अधिकांश विवाह अब भी रिकॉर्ड में नहीं आते। इस क्षेत्र में बाल विवाह भूख, कर्ज व अनिश्चितता से निपटने की कठोर रणनीति है। जलवायु परिवर्तन इस चक्र को और तेज करता है। पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्ययन से पता चलता है कि पिछले दशक में 55 प्रतिशत से अधिक घरों ने अंडरएज विवाहों में वृद्धि दर्ज की है। टेरेस डेस होमस के सर्वेक्षण में खुलासा हुआ कि पथर प्रतिमा और गोसाबा के 90 प्रतिशत लोग पिछले दस वर्षों में सीधे जलवायु आपदाओं का सामना कर चुके हैं, जिससे फसल उत्पादन और खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुई है। ऐसे क्षेत्र में किशोरियों की जल्दी शादी आर्थिक बचाव की रणनीति बन जाती है। प्रवास से जोखिम और बढ़ जाता है। केवल 17 प्रतिशत प्रवासी परिवार अपने साथ पति-पत्नी को ले जाते हैं और सिर्फ 7 प्रतिशत बच्चे को ले जाते हैं, जिससे नाबालिगों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। रिपोर्टें बताती हैं कि बालिकाएं विवाह, जबरन श्रम, मानव तस्करी और विवाह प्रवासन से जुड़ी बढ़ती घटनाओं का सामना कर रही हैं।

मैदान के आंकड़े भले ही अधूरे हों, लेकिन परिणाम स्पष्ट हैं। लड़के परिवार की मदद करने के लिए स्कूल छोड़ देते हैं; लड़कियां घरेलू श्रम, जल्दी गर्भधारण, स्वास्थ्य जोखिम और सीमित गतिशीलता के चक्र में फंस जाती हैं। सर्वेक्षण के मुताबिक, 73.3 प्रतिशत विवाहित लड़कियां अन्य जिलों में पलायन करती हैं, अक्सर अजनबी समुदायों में, बिना यह सुनिश्चित किए कि उनके पति की मंशा या पृष्ठभूमि सुरक्षित भी है। गरीबी और सामाजिक हाशिए पर रहने वाले समुदाय इस संकट को और गहरा कर देते हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के घरों में 44 प्रतिशत बाल विवाह की दर दिखती है।

केनिंग के चिन्मय रे कहते हैं,'कन्याश्री जैसी योजनाएं इन द्वीपों तक नहीं पहुंच पातीं। 'प्रशासनिक बाधाएं, कड़ा दस्तावेज़ीकरण, और राजनीतिक उपेक्षा हाशिए पर रहने वाले परिवारों को लाभ नहीं दिलातीं। प्रवर्तन की कमी बच्चों को असुरक्षित छोड़ देती है और पीड़ितों को मदद नहीं मिलती।' टेरेस डेस होमस के सर्वेक्षण के अनुसार सुंदरबन की दो-तिहाई बालिकाएं अपनी शादी को पिछले आपदाओं से जोड़ती हैं। कोविड-19 लॉकडाउन ने इन समस्याओं को और बढ़ा दिया। स्कूल बंद होने से सुरक्षा की जगहें छिन गईं और बच्चे घरों में सीमित हो गए, जहां गरीबी, कर्ज और निराशा जीवित रहने की दिशा तय करती हैं। पठानखली गांव की 14 वर्षीय कल्याणी गेयन ने स्कूल छोड़ दिया, अपनी किताबें फटे कपड़े में बांधकर, क्योंकि उसकी मां फसल की विफलता के कर्ज चुकाने में संघर्ष कर रही थी। मधुपुर ढेला की 16 वर्षीय प्रिया जाना ने 2024 के तूफान में अपना घर खो दिया। खारे पानी ने खेतों को बर्बाद कर दिया। विकल्पों की कमी के कारण उसके माता-पिता ने उसके विवाह का निर्णय लिया। स्कूल तटबंधों के साथ-साथ टूटते हैं। मौसुनी कोऑपरेटिव स्कूल, द्वीप का एकमात्र माध्यमिक विद्यालय, चिंता बढ़ाने वाली ड्रॉपआउट दर का गवाह है। प्रधानाध्यापक बिनय शि बताते हैं कि पिछले दो वर्षों में 14-18 वर्ष के लगभग 15-20 प्रतिशत छात्र स्कूल छोड़ चुके हैं, तूफानों, गरीबी और जिम्मेदारियों के दबाव में।

मत्स्य और आजीविका विशेषज्ञ डॉ. अनिमेष राय कहते हैं, 'आय बढ़ी नहीं, नावें कम हैं, और बाल विवाह दरवाजे पर खड़ा है' । बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर काले पानी में नाव से यात्रा करते हैं। कार्यकर्ता सर्मिष्ठा दत्ता गुप्ता कहती हैं, 'बाल विवाह कानून केवल कागज़ों पर है। लड़कियों और लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 और 21 वर्ष है, लागू करना उन द्वीपों में विफल होता है, जहां सड़क की जगह नावें हैं और तूफान जीवन तय करते हैं। युवा दुल्हनें कई तरह के नुकसान झेलती हैं—उच्च जोखिम वाला गर्भधारण, एनीमिया, शिक्षा रुकना, मानसिक आघात और घरेलू बंदी। फिर भी, आशा की किरणें बची हैं। नूर स्कूल लौट गई; रूपा देवी स्वरोजगार समूह चलाती हैं; सालवीना ने दो बाल विवाह रोके; अंजलि पुलिस के साथ लड़कियों को बचाने में सहयोग करती हैं। उनका प्रतिरोध संस्थागत खामियों के बीच क्षमता की झलक दिखाता है। विशेषज्ञ जोर देते हैं कि प्रणालीगत समाधान जरूरी हैं-आपदा-प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा, बिना बाधा वाली शिक्षा, आजीविका सुरक्षा, किशोर स्वास्थ्य सेवाएं और जवाबदेह प्रवर्तन।

सुदूर द्वीपों में बाल विवाह को 'परंपरा' कहकर व्याख्यायित करना गलत है। सुंदरबन में, खारी मिट्टी, मुश्किल होता मछली पालन, टूटते तटबंध और बार-बार के चक्रवात आजीविका छीनते हैं। कमजोर आर्थिक स्थिति में जल्दी विवाह जीवन रक्षा की रणनीति बन जाता है- आपदा से निपटने की एक हताश कोशिश। लेकिन हताशा नीति की जगह नहीं ले सकती। साक्ष्य बताते हैं कि जब वित्तीय प्रोत्साहन को निरंतर शिक्षा, किशोर स्वास्थ्य सेवाओं और सामुदायिक निगरानी से जोड़ा जाता है, तब बाल विवाह में कमी आती है।

विस्थापित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, दूरस्थ द्वीपों में कार्यशील माध्यमिक स्कूल, बाढ़ के दौरान स्वास्थ्य केंद्र, महिला प्रधान परिवारों के लिए रोजगार और मोबाइल प्रवर्तन तंत्र शामिल होना चाहिए। पर्यावरण नीति और लैंगिक न्याय में समन्वय बिना, हर तूफान प्रगति को मिटा सकता है।

प्रेरणा

जहां रहेगा, रौशनी लुटाएगा: अदब के आफ़ताब वसीम

उर्दू और हिंदी अदब की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं, जो केवल शायर नहीं रहते, बल्कि एक एहसास, एक रौशनी और एक तहज़ीब बन जाते हैं। वसीम बरेलवी ऐसा ही एक नाम है, जिनकी शायरी ने सीमाओं, भाषाओं और पीढ़ियों की दीवारों को पार करते हुए दिलों में एक खास मुकाम बनाया है। उनकी आवाज़ में न केवल अल्फ़ाज़ की मिठास है, बल्कि उसमें जीवन के गहरे अनुभव, संवेदनाओं की तपिश और इंसानियत की खुशबू भी शामिल है। यही वजह है कि उनकी शायरी को भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपार लोकप्रियता हासिल हुई है।

वसीम बरेलवी की शायरी का जादू इस बात में छिपा है कि वह सीधे दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है। उनकी ग़ज़लों और नज़्मों में जीवन के छोटे-छोटे अनुभव इतने खूबसूरत अंदाज़ में ढले होते हैं कि सुनने वाला खुद को उनमें ढूंढने लगता है। वे दर्द को भी इस तरह बयान करते हैं कि वह बोझ नहीं, बल्कि एक सुकून बन जाता है। यही उनकी कला की सबसे बड़ी ताकत है।

उत्तर प्रदेश के बदायूं से निकलकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचने वाले इस शायर की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित साहित्यिक विशेषांक बार-बार प्रकाशित होते रहे हैं। 1996 में 'लम्हें-लम्हें' पत्रिका ने जब पहला विशेषांक प्रकाशित किया, तो वह केवल एक साहित्यिक प्रयास नहीं था, बल्कि एक शायर के प्रति सम्मान और प्रेम की अभिव्यक्ति थी। इसके बाद 2006 और 2008 में दोबारा उसी विषय पर विशेषांक का प्रकाशन यह साबित करता है कि वसीम बरेलवी की लोकप्रियता समय के साथ कम नहीं हुई, बल्कि और गहरी होती चली गई।

हाल ही में प्रकाशित विशेषांक 'वसीम बरेलवी : जहां रहेगा रौशनी लुटाएगा' इस परंपरा का एक और सशक्त उदाहरण है। इस संकलन में देश के शीर्ष साहित्यकारों, शायरों और बुद्धिजीवियों की 58 रचनाएं शामिल हैं, जो बरेलवी के व्यक्तित्व और उनके सृजन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हैं। इस विशेषांक का संयोजन साहित्य प्रेमी नीरज जैन ने किया है और संपादन फारुक अर्गली ने। यह केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि एक ऐसा दस्तावेज़ है, जो एक महान शायर की पूरी यात्रा को समेटने की कोशिश करता है।

इस संकलन की सबसे खास बात यह है कि इसमें 'वसीम की कहानी वसीम की जबानी' शीर्षक से एक विस्तृत बातचीत भी शामिल है, जो हसीब सोज़ द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस बातचीत में वसीम बरेलवी ने अपने जीवन, संघर्षों और रचनात्मक यात्रा के कई अनछुए पहलुओं को साझा किया है। यह लेख पाठकों को न केवल उनके शायर के रूप से, बल्कि एक इंसान के रूप में भी करीब लाता है।

अगर हम उनके व्यक्तित्व की बात करें, तो उसमें एक अद्भुत सादगी और आत्मीयता दिखाई देती है। वे अपने चाहने वालों के साथ जिस तरह का संबंध रखते हैं, वह आज के समय में बहुत कम देखने को मिलता है। नीरज जैन के साथ उनका रिश्ता इसका एक सुंदर उदाहरण है। पुस्तक में उन्होंने जिस भावुकता के साथ नीरज जैन के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है, वह यह दिखाता है कि उनके लिए रिश्ते केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि दिल से जुड़े होते हैं। 2023 में हुए एक कार हादसे के बाद नीरज जैन ने जिस तरह उनकी सेवा की, उसे उन्होंने अपने बेटे के समान बताया। यह प्रसंग उनके व्यक्तित्व की गहराई और मानवीय संवेदनाओं को उजागर करता है।

इस संकलन में महान शायर फ़िराक़ गोरखपुरी की अभिव्यक्ति भी शामिल है, जो 'मेरा महबूब शायर' शीर्षक से प्रस्तुत की गई है। फ़िराक़ गोरखपुरी जैसे दिग्गज शायर द्वारा दी गई यह सराहना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। वे लिखते हैं कि वसीम की शायरी में ज्ञान और विवेक की गहरी परतें हैं, जो केवल बौद्धिक नहीं, बल्कि भावनात्मक स्तर पर भी पाठक को छूती हैं। उनके अनुसार, वसीम की शायरी जीवन के अनुभवों को न केवल व्यक्त करती है, बल्कि उन्हें और अधिक गहराई से महसूस करने की क्षमता भी देती है।

वसीम बरेलवी की शायरी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह समय के साथ पुरानी नहीं होती। उनके अल्फ़ाज़ हर दौर में उतने ही प्रासंगिक लगते हैं, जितने अपने समय में थे। चाहे वह मोहब्बत की बात हो, दर्द की अभिव्यक्ति हो या समाज की विडंबनाओं पर टिप्पणी—हर विषय पर उनकी पकड़ मजबूत और प्रभावशाली है। उनकी शायरी में एक ऐसी सार्वभौमिकता है, जो हर इंसान को अपने करीब महसूस होती है।

इस विशेषांक में शामिल रंगीन चित्र भी उनकी यात्रा को जीवंत बना देते हैं। ये चित्र केवल तस्वीरें नहीं, बल्कि उनके जीवन के अलग-अलग पड़ावों के गवाह हैं। इन्हें देखकर पाठक न केवल उनके शब्दों से, बल्कि उनके व्यक्तित्व के दृश्य पक्ष से भी जुड़ पाता है।

डब्ल्यू.बी.एस फाउंडेशन के तत्वावधान में प्रकाशित यह संग्रहणीय अंक अदब के प्रेमियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। यह केवल एक शायर को श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि उस पूरी परंपरा का सम्मान है, जिसने उर्दू और हिंदी साहित्य को इतना समृद्ध बनाया है। अंततः, यह कहना गलत नहीं होगा कि वसीम बरेलवी केवल एक शायर नहीं, बल्कि एक रौशनी हैं—ऐसी रौशनी, जो जहां भी जाएगी, अपने आसपास उजाला ही फैलाएगी। उनकी शायरी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी और अदब की दुनिया में उनका नाम हमेशा सम्मान और प्रेम के साथ लिया जाएगा।

अक्षय तृतीया पर्व है लोक से लोकोत्तर की दिव्य यात्रा

अक्षय तृतीया महापर्व का न केवल सनातन परम्परा में बल्कि जैन परम्परा में विशेष महत्व है। इसका लौकिक और लोकोत्तर-दोनों ही दृष्टियों में महत्व है। अक्षय शब्द का अर्थ है कभी न खत्म होने वाला। संस्कृत में, अक्षय शब्द का अर्थ है 'समृद्धि, आशा, खुशी, सफलता', जबकि तृतीया का अर्थ है 'चंद्रमा का तीसरा चरण'। इस त्यौहार के साथ-साथ एक अबूझा मांगलिक एवं शुभ दिन भी है, जब बिना किसी मुहूर्त के विवाह एवं मांगलिक कार्य किये जा सकते हैं। विभिन्न सांस्कृतिक एवं मांगलिक ढांचों में ढले अक्षय तृतीया पर्व में हिन्दू-जैन धर्म, संस्कृति एवं परम्पराओं का अनूठा संगम है। इस प्रकार अक्षय तृतीया पर किए गए कार्यों जैसे जप-तप, यज्ञ, पितृ-तर्पण, दान-पुण्य आदि का साधक को अक्षय फल प्राप्त होता है। भगवान आदिनाथ ने ही सबसे पहले समाज में दान का महत्व समझाया था, इसलिए इस दिन पर जैन धर्म के लोग आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान करते हैं। रास्ते चाहे कितने ही भिन्न हों पर इस पर्व त्यौहार के प्रति सभी जाति, वर्ग, वर्ण, सम्प्रदाय और धर्मों का आदर-भाव अभिन्नता में एकता का प्रिय संदेश दे रहा है। आज के युद्ध, आतंक, आर्थिक प्रतिस्पर्धा एवं अशांति के समय में संयम एवं तप की, भौतिकता एवं आध्यात्मिकता की अक्षय परम्परा को जन-जन की जीवनशैली बनाने की जरूरत है।अक्षय तृतीया यह केवल एक तिथि नहीं, बल्कि भारतीय चेतना की उस अखंड धारा का प्रतीक है, जो जीवन को क्षणभंगुरता से उठाकर 'अक्षयता' की ओर ले जाती है। 'अक्षय' अर्थात् जो कभी क्षीण न हो, जो निरंतर प्रवहमान रहे, ऐसी ही भावना का यह पर्व है, जो हमारे लौकिक व्यवहार से लेकर लोकोत्तर साधना तक, हर स्तर पर गहन अर्थ रखता है। यह दिन केवल शुभारंभ का नहीं, बल्कि आत्मारंभ का भी दिन है। भारतीय परंपरा में अक्षय तृतीया को 'अबूझ मुहूर्त' कहा गया है-अर्थात् ऐसा समय, जिसमें किसी विशेष गणना या ज्योतिषीय विचार की आवश्यकता नहीं होती। यह स्वयं ही शुभता का पर्याय है। यही कारण है कि इस दिन विवाह, गृहप्रवेश, व्यापारारंभ जैसे अनेक मांगलिक कार्य बिना किसी संकोच के सम्पन्न किए जाते हैं। यह विश्वास केवल आस्था नहीं, बल्कि उस सांस्कृतिक अनुभव का परिणाम है, जिसने इस दिन को 'सर्वसिद्धिदायक' मान्यता प्रदान की है।

लौकिक दृष्टि से देखें तो अक्षय तृतीया भारतीय अर्थव्यवस्था और श्रम-संस्कृति से गहराई से जुड़ी हुई है। यह दिन किसानों के लिए नई आशा का संदेश लेकर आता है। प्राचीन काल में राजाओं द्वारा श्रेष्ठ किसानों को बीज भेंट करने की परंपरा केवल सम्मान का प्रतीक नहीं थी, बल्कि कृषि को राष्ट्र की आत्मा मानने का सजीव प्रमाण थी। यह विश्वास कि इन बीजों से उत्पन्न अन्न कभी समाप्त नहीं होगा, दरअसल उस श्रम और प्रकृति के समन्वय पर आस्था थी, जो भारतीय जीवन का आधार है। कुम्हारों, शिल्पकारों, पशुपालकों-विशेषकर बैलों के लिए भी यह दिन विशेष महत्व रखता है। यह पर्व हमें यह स्मरण कराता है कि सृजन, श्रम और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता ही समृद्धि का वास्तविक आधार है। किन्तु अक्षय तृतीया का वास्तविक सौंदर्य उसके लोकोत्तर आयाम में प्रकट होता है, जहाँ यह पर्व आत्मशुद्धि, तप और साधना का महापर्व बन जाता है। जैन परंपरा में यह दिन विशेष रूप से पूज्य है, क्योंकि इसका संबंध प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना से जुड़ा हुआ है। यह वह दिन है, जब दीर्घकालीन तपस्या के उपरांत उनका पारणा हुआ, एक ऐसा क्षण, जिसने तप को तृप्ति और साधना को पूर्णता प्रदान की।

कथा के अनुसार, जब भगवान ऋषभदेव ने राजपाट त्यागकर संन्यास धारण किया, तब एक वर्ष से अधिक समय तक उन्हें उचित आहार नहीं मिला। यह केवल भौतिक अभाव नहीं था, बल्कि उस युग की सामाजिक अपरिपक्वता का द्योतक था, जहाँ लोग 'अहिंसक आहार' और 'संयमित जीवन' की अवधारणा से अनभिज्ञ थे। अंततः हस्तिनापुर में राजकुमार श्रेयांस ने उन्हें इक्षुरस अर्पित कर उनकी तपस्या का पारणा कराया। उस क्षण 'अहोदानम्, अहोदानम्' की ध्वनि गूंजी, यह केवल एक आह्लाद नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक चेतना का उद्घोष था, जिसने दान, संयम और साधना को एक नई दिशा दी। यही कारण है कि अक्षय तृतीया जैन साधकों के लिए 'वर्षीतप' जैसे महान तप-अनुष्ठानों का पूर्णाहुति दिवस है। एक वर्ष तक एकान्तर उपवास करने वाले साधक इस दिन पारणा करते हैं। यह तप केवल शरीर को कष्ट देने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा को निर्मल करने की प्रक्रिया है। यह हमें सिखाता है कि भोग से नहीं, त्याग से जीवन अक्षय बनता है।

अक्षय तृतीया का आध्यात्मिक संदेश अत्यंत गहन है। यह हमें बताता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल संसाधनों का संचय नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि है। भारतीय संस्कृति में 'आत्मा' को सर्वोपरि सत्य माना गया है, और उसकी खोज को जीवन की सर्वोच्च साधना। यह पर्व उसी खोज का निमंत्रण है, एक ऐसा निमंत्रण, जो हमें बाह्य जगत से भीतर की यात्रा पर ले जाता है। ऋषभदेव का जीवन इस संदर्भ में अत्यंत प्रेरणादायक है। 'ऋषभ' शब्द का एक अर्थ बैल भी है-जो श्रम, धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है और दूसरा अर्थ है तीर्थंकर-जो आत्मोद्धार और लोकमंगल का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार उनका जीवन भौतिक और आध्यात्मिक-दोनों आयामों का अद्भुत समन्वय है। उन्होंने समाज को कृषि, शिल्प, व्यापार जैसी जीवनोपयोगी विधाएं दीं, और साथ ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी दिखाया। यही समग्रता अक्षय तृतीया के दर्शन में भी झलकती है। आज के संदर्भ में यह पर्व और भी प्रासंगिक हो उठता है। जब मानव जीवन भौतिक उपलब्धियों की दौड़ में उलझा हुआ है, तब अक्षय तृतीया हमें संतुलन का पाठ पढ़ाती है। यह हमें याद दिलाती है कि केवल भौतिक समृद्धि से जीवन पूर्ण नहीं होता। यदि भीतर शांति नहीं, तो बाहरी वैभव भी निरर्थक है। और यदि भीतर संतोष है, तो सीमित साधनों में भी जीवन अक्षय बन सकता है।

अभियान

अक्षय पुण्य का अमर पर्व: अक्षय तृतीया 2026 की संपूर्ण महिमा, सही मुहूर्त, पूजा-विधि और जीवन में इसका गहरा अर्थ

भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में कुछ पर्व ऐसे होते हैं, जो केवल उत्सव नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाले आध्यात्मिक अवसर होते हैं। अक्षय तृतीया उन्हीं विशेष पर्वों में से एक है, जिसे 'अनंत फल देने वाला दिन' कहा जाता है। 'अक्षय' का अर्थ है—जो कभी समाप्त न हो। यानी इस दिन किए गए पुण्य कर्म, दान, जप, तप और शुभ कार्यों का फल अनंत काल तक बना रहता है। यही कारण है कि इस तिथि को अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है।

यह पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है और पूरे भारत में अलग-अलग रूपों में मनाया जाता है। कहीं इसे 'आखा तीज' कहा जाता है, तो कहीं यह नए कार्यों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन सतयुग और त्रेतायुग का आरंभ हुआ था, जिससे इस तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है। साथ ही, यह भी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है।

पंचांग के अनुसार, वर्ष 2026 में

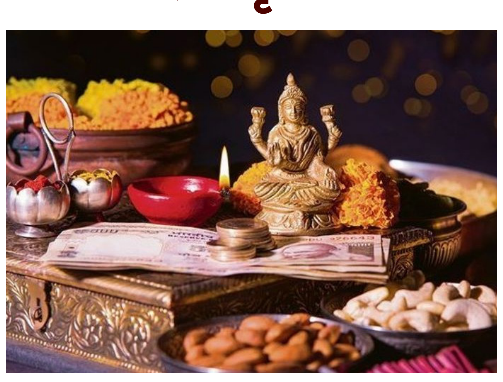

अक्षय तृतीया की तिथि 19 अप्रैल को सुबह 10:49 बजे से प्रारंभ होकर 20 अप्रैल को सुबह 7:27 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार पर्व 20 अप्रैल को मनाया जाएगा, लेकिन 19 अप्रैल को ही तिथि लग जाने के कारण उसी दिन पूजा का विशेष महत्व है। 19 अप्रैल को सुबह 10:49 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक का समय प्रमुख शुभ मुहूर्त माना गया है। इसके अलावा दिनभर में अन्य शुभ काल भी उपलब्ध हैं, जिनमें पूजा, दान और खरीदारी करना अत्यंत लाभकारी होता है।

इस पावन दिन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन इनकी विधिपूर्वक पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि, वैभव और शांति का वास होता है। पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ और preferably पीले वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद धूप-दीप, पुष्प, तुलसी पत्र और नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु सहस्रनाम या लक्ष्मी मंत्र का जाप करें और अंत में आरती कर प्रसाद वितरित करें।

अक्षय तृतीया का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है—दान। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जल, सत्तू, चावल, दही और दूध का दान करना अत्यंत फलदायी माना गया है। गर्मी के मौसम को देखते हुए प्यासे लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करना, जल से भरे घड़े दान करना या राहगीरों के लिए प्याऊ लगाना भी बहुत पुण्य का कार्य माना गया है।

इस दिन को 'अबूझ मुहूर्त' कहा जाता है, यानी किसी भी शुभ कार्य के लिए अलग से मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार शुरू करना, वाहन खरीदना या किसी भी नई योजना की शुरुआत इस दिन की जा सकती है। यही कारण है कि इस दिन को साल के सबसे शुभ दिनों में गिना जाता है।

अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की परंपरा भी बहुत प्रचलित है। माना जाता है कि इस दिन सोना खरीदने से धन-समृद्धि में वृद्धि होती है और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। लेकिन यदि कोई सोना खरीदने में सक्षम न हो, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ अन्य वस्तुओं का उल्लेख किया गया है, जिन्हें खरीदना भी शुभ माना गया है।

मिट्टी के बर्तन खरीदना मंगल ग्रह को मजबूत करता है और जीवन की बाधाओं को दूर करता है। रूई खरीदना शुक्र ग्रह से संबंधित है, जिससे सौंदर्य और सुख-सुविधाओं में वृद्धि होती है। हल्दी की गांठ खरीदने से गुरु ग्रह मजबूत होता है और जीवन में स्थिरता आती है। पीली सरसों और पीली कौड़ी खरीदना भी धन और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। तांबा खरीदना सूर्य ग्रह को बल देता है, जिससे आत्मविश्वास और मान-सम्मान में वृद्धि होती है।

अब बात करते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। दीपक जलाकर घर को रोशन रखना चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांसाहार, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। यह दिन शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक है, इसलिए सादा और पवित्र भोजन ही ग्रहण करना चाहिए।

इसके अलावा क्रोध, विवाद और नकारात्मक सोच से भी बचना चाहिए। इस दिन किए गए हर कर्म का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए सकारात्मक सोच और व्यवहार बनाए रखना आवश्यक है। उधार का लेन-देन भी इस दिन अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन लिया गया कर्ज लंबे समय तक बना रहता है और आर्थिक समस्याओं को जन्म दे सकता है। चमड़े से बनी वस्तुएं खरीदना भी इस दिन वर्जित माना गया है।

अक्षय तृतीया केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे दर्शन को भी प्रस्तुत करती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों, दया, करुणा और संतोष से आती है। इस दिन किया गया छोटा सा दान भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है।

आधुनिक जीवन की भागदौड़ में जहां लोग तनाव और असंतोष से घिरे रहते हैं, वहां अक्षय तृतीया जैसे पर्व हमें रुककर सोचने का अवसर देते हैं। यह दिन हमें अपने भीतर झांकने, अपनी गलतियों को सुधारने और एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है।

अंततः, अक्षय तृतीया केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अवसर है—जीवन में सकारात्मकता, समृद्धि और शांति लाने का। यदि इस दिन श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से पूजा, दान और अच्छे कर्म किए जाएं, तो न केवल भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, बल्कि आत्मिक संतोष और मानसिक शांति भी मिलती है। यही इस पावन पर्व का वास्तविक संदेश है—अच्छे कर्म करें, सकारात्मक रहें और जीवन को सार्थक बनाएं।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

"अब नहीं आऊंगा दोस्त...": एलपीजी संकट ने छीना रोजगार सूरत से लौटते मजदूरों की आंखों में दर्द और बेबसी

सूरत। हाथ में बैग, चेहरे पर गहरी मायूसी और आंखों में छलकते आंसू—यह सिर्फ एक युवक की कहानी नहीं, बल्कि हजारों मजदूरों की उस हकीकत का आईना है, जो आज रोजगार छिन जाने के बाद मजबूरी में अपने घर लौट रहे हैं। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन से सामने आए एक वीडियो ने इस दर्द को देश के सामने ला दिया है, जिसमें एक युवक बार-बार कहता नजर आता है—"अब नहीं आऊंगा दोस्त बता देना, अब नहीं आऊंगा।"

यह शब्द सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि उस टूटते भरोसे और बिखरते सपनों की गूंज हैं, जो कभी बेहतर जिंदगी की तलाश में इस औद्योगिक शहर तक पहुंचे थे। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि वही शहर उन्हें अपनाने में असमर्थ दिख रहा है।

मिडिल-ईस्ट में जारी तनाव और उससे पैदा हुए एलपीजी संकट का असर अब सीधे भारत के औद्योगिक शहरों में दिखाई देने लगा है। खासतौर पर सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो देश की आर्थिक धड़कन मानी जाती है, इस संकट से बुरी तरह प्रभावित हुई है। गैस की कमी ने उत्पादन को धीमा कर दिया है, जिससे फैक्ट्रियों में काम ठप पड़ने लगा है।

आंकड़ों के अनुसार, जहां पहले रोजाना करीब 6.5 करोड़ मीटर कपड़े का उत्पादन होता था, वह अब घटकर लगभग 4.5 करोड़ मीटर रह गया है। यह गिरावट सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि लाखों मजदूरों की रोजी-रोटी पर सीधा असर डाल रही है। उद्योगों को रोजाना लगभग 15 हजार गैस सिलेंडर की जरूरत होती है, लेकिन सप्लाई में आई कमी ने उत्पादन की रफ्तार तोड़ दी है।

इसका सबसे बड़ा असर उन मजदूरों पर पड़ा है, जो दूसरे राज्यों—खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार—से सूरत में काम करने आते हैं। अनुमान है कि अब तक करीब 30 प्रतिशत मजदूर, यानी लगभग 3 लाख लोग, शहर छोड़ चुके हैं। यह पलायन अचानक नहीं, बल्कि पिछले एक-दो महीनों से लगातार जारी है।

उधना रेलवे स्टेशन पर उमड़ती भीड़ इस संकट की सबसे सजीव तस्वीर बनकर सामने आई है। यहां रोजाना हजारों की संख्या में लोग अपने घर लौटने के लिए पहुंच रहे हैं। ट्रेनों में सीटों के लिए मारामारी, प्लेटफॉर्म पर अफरा-तफरी और थके-हारे चेहरों की लंबी कतारें—यह सब कुछ इस बात का संकेत है कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं।

वीडियो में दिख रहा युवक भी उन्हीं लाखों लोगों में से एक है, जो कभी उम्मीद लेकर सूरत आया था। लेकिन अब उसके शब्दों में निराशा साफ झलकती है। "अब नहीं आऊंगा"—यह केवल एक निर्णय नहीं, बल्कि उस भरोसे के टूटने का संकेत है, जो उसे यहां तक खींच लाया था।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक भी है। जब बड़ी संख्या में मजदूर एक साथ शहर छोड़ते हैं, तो इसका असर न सिर्फ उद्योगों पर पड़ता है, बल्कि शहर की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे पर भी पड़ता है।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, बढ़ती भीड़ के पीछे केवल एलपीजी संकट ही नहीं, बल्कि गर्मियों की छुट्टियां भी एक कारण हैं। लेकिन यह भी सच है कि गैस की कमी ने इस स्थिति को और गंभीर बना दिया है। यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ने से रेलवे की व्यवस्थाएं भी दबाव में आ गई हैं।

हालांकि, रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाने की कोशिश की है, लेकिन यह बढ़ती मांग के सामने अपर्याप्त साबित हो रही हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई बार पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ रहा है।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है—क्या हमारे औद्योगिक ढांचे में इतनी मजबूती है कि वह ऐसे बाहरी संकटों का सामना कर सके? और अगर नहीं, तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा हमेशा मजदूरों को ही क्यों भुगतना पड़ता है?

सूरत की सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशनों तक फैली यह बेचैनी सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था की भी झलक है, जहां सबसे कमजोर वर्ग सबसे पहले प्रभावित होता है।

आज वह युवक अपने गांव लौट रहा है, लेकिन उसके शब्द लंबे समय तक गूंजते रहेंगे—"अब नहीं आऊंगा दोस्त"। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि उस दर्द की कहानी है, जिसे समझना और सुलझाना अब बेहद जरूरी हो गया है।

टाटा ट्रस्ट्स का बड़ा कदम: बाई हीराबाई ट्रस्ट में बदले जाएंगे ट्रस्टी नियम, समावेशिता की ओर बढ़ता कदम

नई दिल्ली। देश के प्रतिष्ठित परोपकारी संगठनों में शामिल टाटा ट्रस्ट्स ने बाई हीराबाई ट्रस्ट से जुड़े ट्रस्टी नियुक्ति नियमों में बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। इस कदम को न केवल एक प्रशासनिक सुधार, बल्कि ट्रस्ट की विचारधारा को आधुनिक और समावेशी बनाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है।

टाटा ट्रस्ट्स के न्यासियों ने निर्णय लिया है कि ट्रस्ट डीड में मौजूद उन पुराने और प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को बदला जाएगा, जो ट्रस्टी बनने की पात्रता को सीमित करते हैं। इनमें सबसे प्रमुख प्रावधान वह है, जिसमें गैर-यहूदियों या विशेष समुदाय से बाहर के लोगों को ट्रस्टी बनने से रोका गया था। अब इन शर्तों को संशोधित करने के लिए सक्षम प्राधिकरण के समक्ष औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

यह निर्णय हाल ही में सामने आए एक विवाद के बाद लिया गया है। पूर्व ट्रस्टी मेहली मिस्त्री ने महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर के समक्ष शिकायत दर्ज कर ट्रस्ट में हुई कुछ नियुक्तियों को चुनौती दी थी। शिकायत में कहा गया था कि वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह की नियुक्ति ट्रस्ट डीड में निर्धारित शर्तों—जैसे पारसी जरथुस्त्री धर्म से होना और मुंबई निवासी होना—के अनुरूप नहीं है।

इस विवाद के बीच वेणु श्रीनिवासन ने हाल ही में ट्रस्ट से इस्तीफा भी दे दिया। शुरुआत में उन्होंने इसे व्यक्तिगत व्यस्तताओं का कारण बताया, लेकिन बाद में स्पष्ट किया कि यह निर्णय ट्रस्ट प्रबंधन के अनुरोध पर लिया गया था। इस घटनाक्रम ने ट्रस्ट के नियमों और उनकी प्रासंगिकता पर सवाल खड़े कर दिए थे।

17 अप्रैल को हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में, जिसकी अध्यक्षता नोएल टाटा ने की, ट्रस्ट की गतिविधियों की व्यापक समीक्षा की गई। इस बैठक में न केवल मौजूदा विवाद पर चर्चा हुई, बल्कि यह भी तय किया गया कि ट्रस्ट डीड में मौजूद विसंगतियों को दूर करना जरूरी है।

बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि समय के साथ बदलते सामाजिक और कानूनी परिदृश्य को देखते हुए ट्रस्ट के नियमों को भी अपडेट किया जाना चाहिए। विशेष रूप से उन प्रावधानों को हटाने या संशोधित करने की आवश्यकता महसूस की गई, जो आज के दौर में असंगत या भेदभावपूर्ण माने जा सकते हैं।

टाटा ट्रस्ट्स ने अपने आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया है कि संगठन की मूल विचारधारा हमेशा से समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता और जनसेवा पर आधारित रही है। ऐसे में ट्रस्टी पात्रता से जुड़े प्रतिबंधात्मक नियम इस व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं थे। यही कारण है कि अब इन्हें बदलने की पहल की जा रही है।

दिलचस्प बात यह है कि वर्ष 2000 में एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश से प्राप्त कानूनी राय के आधार पर गैर-यहूदियों की नियुक्ति पहले भी की जाती रही है। यानी व्यवहारिक रूप से ट्रस्ट पहले ही इन सीमाओं को आंशिक रूप से पार कर चुका था, लेकिन अब इसे औपचारिक रूप देने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है।

बाई हीराबाई जमशेदजी टाटा नवसारी चैरिटेबल इंस्टिट्यूशन एक गैर-शेयरधारिता न्यास है, जिसकी परिसंपत्तियां और गतिविधियां सीमित दायरे में संचालित होती हैं। हालांकि इसका दायरा सीमित है, लेकिन इसके नियमों में बदलाव का व्यापक संदेश पूरे परोपकारी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल कानूनी जटिलताओं को दूर करेगा, बल्कि ट्रस्ट की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को भी मजबूत करेगा। साथ ही, यह अन्य ट्रस्टों और संस्थाओं के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है, जो अभी भी पुराने और सीमित दायरे वाले नियमों के तहत काम कर रहे हैं। यह पहल ऐसे समय में सामने आई है, जब देश में कॉरपोरेट गवर्नेंस और संस्थागत पारदर्शिता पर लगातार जोर दिया जा रहा है।

कर्ज की रफ्तार और घटते जोखिम: मजबूत नींव पर आगे बढ़ता भारतीय बैंकिंग सेक्टर

नई दिल्ली। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा नजर आ रहा है, जहां स्थिरता, सुधार और विकास—तीनों के संकेत एक साथ दिखाई दे रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में जिस तरह बैंकों ने अपनी बैलेंस शीट को दुरुस्त किया है, खराब कर्ज पर नियंत्रण पाया है और पूंजी आधार को मजबूत किया है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि सेक्टर अब एक नई मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है।

फिक्की और इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा किए गए संयुक्त सर्वे ने इस सकारात्मक तस्वीर को और स्पष्ट कर दिया है। जनवरी से फरवरी 2026 के बीच किए गए इस सर्वे में 24 बैंकों—सार्वजनिक, निजी, विदेशी, स्मॉल फाइनेंस और सहकारी—ने भाग लिया और लगभग सभी ने अपनी वित्तीय स्थिति को पहले से बेहतर बताया।

यह सुधार केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि बैंकिंग सेक्टर के कामकाज के हर पहलू में दिखाई दे रहा है। सबसे अहम बदलाव एसेट क्वालिटी में आया है। एक समय था जब एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) बैंकों के लिए सबसे बड़ी चिंता हुआ करते थे, लेकिन अब इन खराब ऋणों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इससे बैंकों की बैलेंस शीट साफ हुई है और उनकी जोखिम उठाने की क्षमता भी बढ़ी है।

एनपीए में कमी के साथ-साथ पूंजी पर्याप्तता अनुपात में सुधार ने भी बैंकों को मजबूती दी है। इसका सीधा असर कर्ज वितरण पर पड़ा है, जहां अब बैंक पहले की तुलना में ज्यादा आत्मविश्वास के साथ ऋण दे रहे हैं। यह आत्मविश्वास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कर्ज की मांग तेजी से बढ़ रही है।

खासतौर पर रिटेल सेक्टर में कर्ज की मांग ने नई ऊंचाई हासिल की है। होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन जैसे उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई सेक्टर भी तेजी से कर्ज ले रहा है, जो देश की आर्थिक गतिविधियों का एक अहम हिस्सा है। यह दोनों क्षेत्र मिलकर क्रेडिट ग्रोथ के प्रमुख इंजन बन गए हैं।

सर्वे में यह भी सामने आया है कि मौजूदा ब्याज दरें फिलहाल संतुलित स्थिति में हैं। इसका मतलब यह है कि न तो कर्ज बहुत महंगा है और न ही इतना सस्ता कि जोखिम बढ़ जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि निकट भविष्य में ब्याज दरों में बड़े बदलाव की संभावना कम है, जिससे कर्ज की मांग पर सकारात्मक असर बना रह सकता है। हालांकि, कुछ सहकारी बैंकों ने हल्की बढ़ोतरी की आशंका जरूर जताई है, लेकिन समग्र तस्वीर स्थिर नजर आती है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी पीएसबी इस समय सबसे ज्यादा आशावादी दिखाई दे रहे हैं। एसेट क्वालिटी में सुधार और कॉरपोरेट सेक्टर में कर्ज की बढ़ती मांग ने इनके दृष्टिकोण को मजबूत किया है। बड़े प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश में बढ़ती गतिविधियां इन बैंकों के लिए नए अवसर लेकर आ रही हैं।

दूसरी ओर, निजी क्षेत्र के बैंक थोड़ा सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। वे जोखिम प्रबंधन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और कर्ज वितरण में संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। विदेशी बैंक भी इसी तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जहां वे कॉरपोरेट निवेश को लेकर सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ रहे हैं।

गैर-खाद्य ऋण यानी नॉन-फूड क्रेडिट की वृद्धि भी इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। सर्वे में शामिल करीब 46 प्रतिशत प्रतिभागियों का मानना है कि इसकी वृद्धि दर 11 से 13 प्रतिशत के बीच रह सकती है। यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि बैंकिंग सेक्टर में कर्ज वितरण की गति आने वाले समय में भी मजबूत बनी रह सकती है।

सेवा क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियां भी इस ग्रोथ को सहारा दे रही हैं। रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स, वित्तीय सेवाएं और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में तेजी से विस्तार हो रहा है, जिससे कर्ज की मांग में इजाफा हो रहा है। यह ट्रेंड भारत की समग्र आर्थिक प्रगति का भी संकेत देता है।

हालांकि, इस सकारात्मक तस्वीर के बीच कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं। इनमें सबसे बड़ी चुनौती साइबर सुरक्षा की है। डिजिटल बैंकिंग के विस्तार ने जहां ग्राहकों के लिए सुविधा बढ़ाई है, वहीं इसके साथ साइबर क्राइम का खतरा भी बढ़ गया है। ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी और फिशिंग जैसे मामलों में वृद्धि ने बैंकों के सामने नई जिम्मेदारी खड़ी कर दी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में बैंकों को अपनी साइबर सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत करना होगा। इसके लिए उन्नत तकनीक, बेहतर निगरानी और ग्राहकों को जागरूक करने जैसे कदम जरूरी होंगे।

कुल मिलाकर, भारतीय बैंकिंग सेक्टर इस समय एक मजबूत बुनियाद पर खड़ा है। एसेट क्वालिटी में सुधार, बढ़ती कर्ज मांग और संतुलित ब्याज दरों ने इसे नई ऊर्जा दी है। अगर यही रफ्तार बनी रहती है और चुनौतियों का सही तरीके से सामना किया जाता है, तो यह सेक्टर देश की आर्थिक वृद्धि में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

एलपीजी संकट की मार: मार्च में खपत 13% घटी, पश्चिम एशिया तनाव से आपूर्ति पर गहराया दबाव

नई दिल्ली। वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव का असर अब भारत की रसोई और उद्योग—दोनों पर साफ दिखने लगा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते टकराव के बीच देश में एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) की खपत में मार्च महीने के दौरान उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2026 में एलपीजी खपत 13 प्रतिशत घटकर 2.379 मिलियन टन रह गई, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने में यह आंकड़ा 2.729 मिलियन टन था। यह गिरावट केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में पैदा हुए असंतुलन, अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर बढ़ते जोखिम और घरेलू वितरण व्यवस्था पर बढ़ते दबाव की कहानी छिपी है।

दरअसल, भारत अपनी कुल एलपीजी जरूरत का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है। इसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे पश्चिम एशियाई देशों की अहम भूमिका होती है। लेकिन हालिया तनाव, विशेषकर होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास बढ़ी अस्थिरता, ने इस आपूर्ति को प्रभावित किया है। होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही पर बढ़ती निगरानी, सुरक्षा जोखिम और हमलों की घटनाओं ने एलपीजी की सप्लाई को धीमा कर दिया है, जिसका सीधा असर भारत जैसे आयात-निर्भर देशों पर पड़ा है।

इस संकट का सबसे बड़ा प्रभाव गैर-घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों पर देखने को मिला है। आंकड़े बताते हैं कि वाणिज्यिक उपयोग में एलपीजी की खपत करीब 48 प्रतिशत तक घट गई, जबकि बल्क उपभोक्ताओं के लिए यह गिरावट 75 प्रतिशत से अधिक रही। होटल, रेस्तरां, कैटरिंग और छोटे उद्योगों में एलपीजी की उपलब्धता सीमित होने के कारण उत्पादन और सेवाओं पर असर पड़ा है। कई क्षेत्रों में कामकाज की गति धीमी हुई है और लागत बढ़ने से व्यापारियों पर अतिरिक्त दबाव बना है। घरेलू स्तर पर भी स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं है। हालांकि सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई है, फिर भी घरेलू एलपीजी खपत में 8.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, जो घटकर 2.219 मिलियन टन रह गई। यह संकेत देता है कि आपूर्ति की कमी और वितरण में चुनौतियों का असर आम लोगों तक भी पहुंचा है। कई जगहों पर सिलेंडर की उपलब्धता में देरी और कीमतों में अस्थिरता ने उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ाई है।

सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ तात्कालिक कदम उठाए हैं। रिफाइनरियों को निर्देश दिया गया है कि वे पेट्रोकेमिकल उत्पादन में कटौती कर एलपीजी उत्पादन बढ़ाएं। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादन बढ़कर 1.4 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष 1.1 मिलियन टन था। यह वृद्धि निश्चित रूप से राहत देने वाली है, लेकिन आयात पर निर्भरता को देखते हुए यह पूरी मांग को संतुलित करने के लिए पर्याप्त नहीं मानी जा रही। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा संकट केवल आपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक ऊर्जा राजनीति का हिस्सा बन चुका है।

केन्याई धावकों का दबदबा: केफर लुबांसी ने चंद्रशेखर हाफ मैराथन में मारी बाजी, 59 मिनट में रचा रिकॉर्ड जैसा प्रदर्शन

चंद्रशेखर हाफ मैराथन के सातवें संस्करण ने एक बार फिर साबित कर दिया कि लंबी दूरी की दौड़ में अंतरराष्ट्रीय स्तर का मुकाबला अब छोटे शहरों तक भी पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के बलिया में आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में केन्या के धावक केफर लुबांसी ने अपनी असाधारण गति और सहनशक्ति का प्रदर्शन करते हुए 21 किलोमीटर की दौड़ मात्र 59 मिनट 5 सेकंड में पूरी कर पहला स्थान हासिल किया। उनका यह समय न केवल प्रभावशाली रहा, बल्कि इस आयोजन के इतिहास में सबसे तेज प्रदर्शनों में भी शामिल हो गया।

सुबह की हल्की ठंड और उत्साह से भरे माहौल के बीच दौड़ की शुरुआत पटपर-पचखोरा मार्ग से हुई, जहां हजारों की संख्या में स्थानीय लोग और खेल प्रेमी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करने के लिए मौजूद थे। सांसद नीरज शेखर ने हरी झंडी दिखाकर इस बहुप्रतीक्षित प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, शुरुआती कुछ किलोमीटर में ही यह स्पष्ट हो गया कि केन्याई धावक अपनी रणनीति और रफ्तार के दम पर बाकी प्रतिभागियों पर भारी पड़ने वाले हैं।

केफर लुबांसी ने शुरुआत से ही संतुलित गति बनाए रखी। उन्होंने पहले 10 किलोमीटर तक अपनी रफ्तार को नियंत्रित रखा और फिर अंतिम चरण में जब बाकी धावक थकान से जूझने लगे, तब उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाकर निर्णायक बढ़त बना ली। उनकी इस रणनीति ने उन्हें जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। फिनिश लाइन पार करते ही दर्शकों की तालियों और जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा।

दूसरे स्थान के लिए मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। भारतीय धावक सचिन यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 59 मिनट 37 सेकंड में दौड़ पूरी की और दूसरा स्थान हासिल किया। उनके और विजेता के बीच महज 32 सेकंड का अंतर रहा, जो इस प्रतियोगिता के उच्च स्तर और प्रतिस्पर्धा की तीव्रता को दर्शाता है। तीसरे स्थान पर भी केन्या के ही धावक केबिछी वाइजली रहे, जिन्होंने एक घंटा 53 सेकंड का समय लिया। हालांकि शीर्ष दो धावकों की तुलना में उनका समय थोड़ा पीछे रहा, लेकिन उन्होंने भी लगातार अपनी गति बनाए रखकर पोडियम स्थान हासिल किया। इस मैराथन में कुल 730 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से केवल 150 धावक ही फिनिश लाइन तक पहुंच सके। यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि 21 किलोमीटर की यह दौड़ कितनी चुनौतीपूर्ण रही। रास्ते में कई धावकों को थकान, मौसम और शारीरिक सीमाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन जो अंत तक टिके रहे, उन्होंने अपने धैर्य और जज्बे का परिचय दिया।

स्थानीय प्रतिभाओं ने भी इस अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वाराणसी के अनिल पटेल ने चौथा स्थान हासिल कर यह दिखाया कि भारतीय धावक भी अब लंबी दूरी की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जुगनू कुमार पांचवें और अभिषेक प्रजापति छठे स्थान पर रहे। इसके अलावा केन्या के चेपके वांग सातवें, बलिया के सोनू राजभर आठवें, नीतीश कुमार नौवें और मध्य प्रदेश के पंकज पटेल दसवें स्थान पर रहे। पंकज पटेल ने 1 घंटा 7 मिनट 15 सेकंड का समय दर्ज किया, जो उनके लिए एक सराहनीय प्रदर्शन रहा। दौड़ के समापन के बाद वीर लोरिक स्पोर्ट्स स्टेडियम में भव्य पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया।

दबाव में मुंबई, लय में गुजरात: अहमदाबाद में आज टकराएंगे दो विपरीत फॉर्म की टीमें

अहमदाबाद। Gujarat Titans और Mumbai Indians के बीच आज होने वाला मुकाबला केवल दो टीमों की भिड़ंत नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और दबाव के बीच सीधी टक्कर भी है। एक ओर गुजरात टाइटंस है, जिसने शुरुआती झटकों के बाद खुद को संभालते हुए जीत की लय पकड़ ली है, तो दूसरी ओर मुंबई इंडियंस है, जो लगातार हार के सिलसिले से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसे में अहमदाबाद का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए सीजन की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है।

गुजरात की टीम जब मैदान पर उतरेगी तो उसके इरादे साफ होंगे—लगातार तीसरी जीत दर्ज कर अंक तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत करना। कप्तान Shubman Gill की अगुवाई में टीम ने हाल के मैचों में जिस तरह संतुलित प्रदर्शन किया है, उसने उन्हें एक खतरनाक इकाई बना दिया है। खासकर बल्लेबाजी में गिल के साथ साई सुदर्शन और Jos Buttler की मौजूदगी विपक्षी गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। इन खिलाड़ियों ने न केवल रन बनाए हैं, बल्कि मुश्किल हालात में पारी को संभालने की जिम्मेदारी भी निभाई है।

इसके उलट मुंबई इंडियंस का हाल कुछ अलग कहानी बयां करता है। Hardik Pandya की कप्तानी में टीम ने सीजन की शुरुआत तो जीत के साथ की, लेकिन उसके बाद लगातार चार हार ने टीम का संतुलन बिगाड़ दिया है। बल्लेबाजी

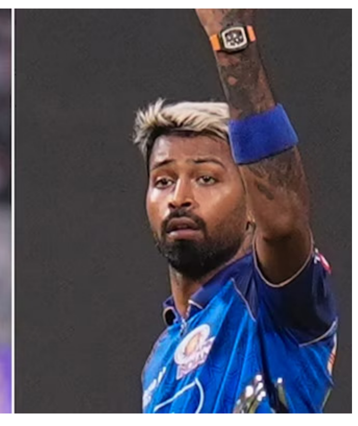

क्रम में निरंतरता की कमी सबसे बड़ी चिंता बनकर उभरी है। Suryakumar Yadav जैसे विस्फोटक बल्लेबाज से अपेक्षित प्रदर्शन नहीं मिल सका है, जबकि तिलक वर्मा भी लय में नजर नहीं आए। शीर्ष क्रम में Rohit Sharma की चोट ने टीम की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, जिससे बल्लेबाजी की जिम्मेदारी कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों पर ही आकर टिक गई है। मुंबई के लिए सबसे बड़ी चुनौती पावरप्ले का उपयोग करना रहा है। शुरुआती ओवरों में न तो रन गति संतोषजनक रही है और न ही विकेट बचाने में सफलता मिली है। इसका असर मध्यक्रम पर पड़ा है, जहां दबाव में बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पा रहे। हार्दिक पंड्या ने जरूर कुछ उपयोगी पारियां खेली हैं, लेकिन कप्तान के तौर पर उन्हें टीम को संकट से बाहर निकालने के लिए और बड़ा योगदान देना होगा।

गेंदबाजी विभाग में भी मुंबई अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई है। Jasprit Bumrah ने किफायती गेंदबाजी की है, लेकिन विकेट न मिलना टीम के लिए चिंता का विषय है। वहीं शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर जैसे गेंदबाज निर्णायक मौकों पर असर नहीं छोड़ पाए हैं। स्पिन आक्रमण में भी निरंतरता का अभाव दिखा है, जिससे विपक्षी टीमों को खुलकर खेलने का मौका मिला।

दूसरी ओर गुजरात की गेंदबाजी अपेक्षाकृत संतुलित नजर आई है। Mohammed Siraj और Kagiso Rabada ने नई गेंद से असर डाला है, जबकि Rashid Khan की मौजूदगी मध्य ओवरों में टीम को मजबूती देती है। हालांकि कुछ मैचों में उतार-चढ़ाव जरूर देखने को मिला है, लेकिन कुल मिलाकर टीम ने परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता दिखाई है।

यह मुकाबला रणनीति और मानसिक मजबूती की भी परीक्षा होगा। गुजरात जहां बिना ज्यादा दबाव के अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर सकती है, वहीं मुंबई के लिए यह मैच 'करो या मरो' जैसा है। अगर मुंबई यहां भी हारती है, तो प्लेऑफ की दौड़ में बने रहना उसके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में टीम को हर विभाग में सामूहिक प्रदर्शन करना होगा।

अहमदाबाद की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, लेकिन यहां की बड़ी बाउंड्री और शाम के समय आने वाली हल्की नमी गेंदबाजों को भी मदद कर सकती है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है, ताकि लक्ष्य का पीछा करते हुए परिस्थितियों का फायदा उठाया जा सके।

दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला केवल अंक तालिका के लिहाज से ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी बेहद अहम है। गुजरात अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी, जबकि मुंबई हर हाल में वापसी की कहानी लिखने के इरादे से मैदान में उतरेगी। दर्शकों के लिए यह मैच रोमांच, दबाव और बड़े खिलाड़ियों के प्रदर्शन से भरपूर रहने की पूरी उम्मीद है।

अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या मुंबई इंडियंस दबाव को पीछे छोड़कर जीत की राह पर लौट पाएगी, या फिर गुजरात टाइटंस अपनी जीत की रफ्तार को और तेज करते हुए इस मुकाबले को भी अपने नाम कर लेगी। अहमदाबाद का मैदान आज इस सवाल का जवाब देगा।

सूरत में अधूरी परियोजनाएं, दलाल-निर्माता का दबाव और निवेशकों की समस्याएं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। शहर और आसपास के इलाकों में बन रही और पूरी हो चुकी परियोजनाओं में, धर्म-वीरू की प्रॉपर्टी ब्रोकर जोड़ी लोगों को ठीक वैसे ही अपनापन महसूस कराती है, जैसे बुलेट ट्रेन में कराया करती थी। ये प्रॉपर्टी ब्रोकर जोड़ी लोगों को वैसा ही एहसास दिलाती है। सरौली से गोदादरा तक के बाज़ारों की परियोजनाएं, रिंग रोड पर स्थित बाज़ार, बिल्डरों द्वारा बनाई गई परियोजनाएं, लंबे समय से अधूरी पड़ी हैं और कई बाज़ार लंबे समय से जर्जर हालत में हैं। इनके पूरा होने की कोई उम्मीद भी नहीं है। ऐसी परियोजनाओं में, ज़रूरतमंद लोगों ने बुकिंग के समय 30%-40% भुगतान करके ब्रोकरों के माध्यम से दुकानें या गोदाम बुक करवाए थे, लेकिन बिल्डरों और ब्रोकरों के माध्यम से निवेश करने वालों को लंबे समय से कोई लाभ नहीं मिला है। वहीं, जिन परियोजनाओं को पूरा हुए 10-12 साल से अधिक समय हो गया है, उनमें लोगों को लंबे समय से कब्ज़ा नहीं मिला है। कई बाज़ार अधूरे निर्माण के कारण जर्जर हालत में हैं।

ऐसे खस्ताहाल बाजारों में, जिन लोगों ने अपनी 30%-40% रकम बेवजह निवेश कर दी है, वे अक्सर बिल्डरों से अपना पैसा वसूलने जाते हैं। इसी बीच, धर्म-वीरू जैसे दो प्रॉपर्टी ब्रोकर अपनी बुलेट कार में ऐसे इलाकों में जाते हैं और पता लगाते हैं कि किसने पैसा निवेश किया है और कब से फंसा हुआ है। वे फंसे हुए लोगों से मिलते हैं, हमदर्दी जताते हैं, उनका विश्वास जीतते हैं और उनसे पूरी जानकारी निकलवा लेते हैं। वे पूछते हैं, "आपके पास क्या सबूत है? अगर डायरी, सौदे के दस्तावेज जैसे सबूत हैं, तो हम तथाकथित प्रॉपर्टी ब्रोकरों के संगठन के सदस्य हैं। इसलिए हम बिल्डरों से आपका फंसा हुआ पैसा निकलवा देंगे।" वे इस तरह से आपका विश्वास जीतते हैं। वे

एक-दूसरे के मोबाइल नंबर और दूसरे कारोबारियों के पते हासिल कर लेते हैं और उनसे संपर्क में रहते हैं। बिल्डरों से मिलने की बात करके हम अपना 10%-15% पैसा वसूल लेंगे और किसी भी बिल्डर से आपका पैसा निकलवा लेंगे। इसलिए, निवेशक और जरूरतमंद लोग इस जोड़े पर भरोसा कर लेते हैं और उन्हें सौदे के दस्तावेजों और डायरियों की फोटोकॉपी दे देते हैं। और वे समुदाय और जाति से घनिष्ठ संबंध बनाकर जरूरतमंदों से पैसे वसूलते हैं। कई बार जरूरतमंद लोग और निवेशक मूल सौदे के दस्तावेज और डायरी भी दे देते हैं। इसके बाद, बिल्डरों से मिलने के बाद, हम खुद को दलाल संघ के सदस्य के रूप में उनसे परिचित कराते हैं और निवेशकों के पैसे के बारे में बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि अगर वे हमें वह पैसा नहीं देते जो उन्हें नहीं मिला है, तो हम बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और उनकी परियोजनाओं के खिलाफ धरना देंगे।

इससे डरकर बिल्डर अपनी इज्जत बचाने के लिए संपत्ति दलालों की जोड़ी से समय मांगता है। और बिल्डरों के साथ जो समझौता हुआ था कि हम निवेशकों और जरूरतमंदों को तीन से छह महीने के भीतर भुगतान कर देंगे, उसे धर्म-वीर की संपत्ति दलाल जोड़ी सादे कागज पर बिल्डरों को भुगतान के संबंध में लिख देती है।

विशेष नोट
धर्म-वीरू की इस प्रॉपर्टी ब्रोकर जोड़ी के नाम, बिल्डरों के नाम, परियोजनाओं के नाम और अन्य ब्रोकरों के नामों के बारे में अधिक जानने के लिए, दैनिक गरवी गुजरात पढ़ते रहें।

इस प्रॉपर्टी ब्रोकर जोड़ी की परेशानियां बढ़ने पर एक कुख्यात प्रोजेक्ट के बिल्डर ने दोनों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई, जिसके चलते उन्हें जेल जाना पड़ा। बाद में अदालत ने दोनों को जमानत दे दी। अन्य ब्रोकरों की आपस में जान-पहचान और इस जोड़ी की एक नामी ब्रोकर से जान-पहचान होने के कारण, इस जोड़ी ने कुछ प्रोजेक्टों में छोटा-बड़ा कारोबार किया था। ब्रोकर एक-दूसरे के प्रोजेक्टों में 0.5% से 1% तक ब्रोकरेज लेते हैं। लेकिन चूंकि यह जोड़ी एक नामी ब्रोकर है, इसलिए वे पैसे नहीं वसूलते, फिर अचानक उनकी वसूली शुरू हो जाती है। फिर, 0.5% से 1% के बजाय, दूसरे पक्ष से, चाहे वह कोई प्रतिष्ठित ब्रोकर हो, निवेशक हो या जरूरतमंद व्यक्ति, 2% से 3% तक शुल्क लिया जाता है। और जब वे कहते हैं कि यह प्रतिशत ब्रोकरेज देना ही होगा, तो वे धौंस जमाने और डराने-धमकाने का सहारा लेते हैं और धर्म-वीरू की भूमिका निभाते हुए जोर-जोर से चिल्लाते और गाली-गलौज करते हैं। फिर वे दूसरे पक्ष के प्रतिष्ठित ब्रोकर को किसी अन्य प्रोजेक्ट के स्थान पर बुलाकर वीरू की भूमिका निभाते हैं और उसके साथ मौज-मस्ती करते हैं। धर्मवीर की बेटी, जो इस धर्म-वीरू जोड़ी की बेटी है, को हाल ही में बार काउंसिल से वकील का प्रमाण पत्र मिला है। इसी वजह से, ये जोड़ी, भले ही उनकी बेटी वकील है, चिल्लाती है और दूसरे पक्ष को गलत मामले में फंसाती है, वरना कहती है कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, मुझे किडनी और लीवर की गंभीर बीमारी है। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम नाराज और परेशान हो जाओगे। इसलिए मुझे पैसे दे दो।

इसलिए, प्रतिष्ठित दलाल स्तब्ध रह गया और धर्म-वीरू द्वारा मनमाने ढंग से तय किए गए प्रतिशत को देने के लिए समय मांगा। प्रतिष्ठित दलाल ने दंपति को अपने मित्र के कार्यालय में बुलाया और एक सादे कागज पर उनकी मनमानी रकम लिख दी। प्रतिष्ठित दलाल ने 1 लाख 91 हजार रुपये की छोटी-बड़ी संपत्तियों की दलाली का वह लिखित दस्तावेज लिया और अपने मित्र के माध्यम से दंपति को उनके कार्यालय में भुगतान कर दिया। लेकिन दंपति को यह नहीं पता कि यह समझौता कहां हुआ और पैसा कहां प्राप्त हुआ और कहां दिया गया। उस मित्र के कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में, प्रतिष्ठित दलाल के मित्र ने दंपति की रसीद और भुगतान के सबूत के तौर पर फुटेज रखी है। दंपति की मानसिकता को समझते हुए, प्रतिष्ठित दलाल के मित्र ने सबूत को एहतियात के तौर पर सुरक्षित रख लिया है।

जिन परियोजनाओं का कब्ज़ा 10 से 12 वर्षों से अधिक समय से नहीं मिला है, उनके बिल्डर इस तरह के गठजोड़ को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि जरूरतमंद और निवेशक, जिन्होंने अन्य दलालों के माध्यम से 30% से 40% निवेश किया है, उन्हें दुकानों या गोदामों का कब्ज़ा नहीं मिला है। लंबे समय बाद, निवेशक उन्हीं दलालों से संपर्क करते हैं जिन्होंने उनके माध्यम से निवेश किया था। और वे दलाल उन्हें बिल्डरों से मिलवाते हैं। लेकिन चूंकि बिल्डर और दलाल एक ही माला के मोती हैं, इसलिए बिल्डर खुलेआम जरूरतमंद और निवेशकों से कहते हैं कि उन्हें उनके द्वारा भुगतान की गई राशि का 30% से 40% वापस मिलेगा या वे अन्य परियोजनाओं में दुकानें, गोदाम, फ्लैट दिलाने की बात करते हैं, चाहे वे उनके दोस्तों की हों या उनकी अपनी परियोजनाएं हों। जब दरें बाजार दर से बहुत अधिक होती हैं और यह एक व्यावसायिक स्थान होता है, तो निवेशक और जरूरतमंद ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और यदि भुगतान की गई राशि उपलब्ध नहीं होती है, तो पैसा वापस कर दिया जाता है और भुगतान की गई राशि का 30% से 40% वापस दे दिया जाता है। और इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। जैसे ही हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध होंगी, हम आपको दे देंगे। ऐसे बिल्डर सरासर घमंड और अहंकार से बातें करते हैं। क्योंकि लेन-देन के नोट या डायरी में लिखे दस्तावेज़ों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। चूंकि बिल्डर यह बात अच्छी तरह जानते हैं और स्थानीय पुलिस एवं उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों से उनके अच्छे संबंध हैं, इसलिए वे बेखौफ रहते हैं। निवेशकों और जरूरतमंदों को इन्हीं दलालों के माध्यम से बताया जाता है कि जो हम देंगे, वही लेना पड़ेगा। बार-बार खुलेआम धमकी दी जाती है कि हमारे प्रोजेक्ट में न आएं और जब वे पैसे लेने जाते हैं, तो बिल्डर जुगल जोड़ी को कॉर्डवर्ड या मोबाइल से कॉल करके निवेशकों और जरूरतमंदों को धमकाते हैं और कहते हैं कि पैसे ले लो। जुगल जोड़ी खुलेआम कहती है कि बिल्डर जो भी दें, वही ले लें। ऐसे दीर्घकालीन प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते क्योंकि वे योजना के विरुद्ध बनाए जाते हैं, अतिरिक्त दुकानें, शोरूम, गोदाम आदि बन जाते हैं और बिल्डर रिश्वतखोरी और विपुल गणेशवाला जैसे भ्रष्ट अधिकारियों के आशीर्वाद से इनका पूरा फायदा उठाते हैं। लेकिन बिल्डरों को इस बात का एहसास नहीं है कि डायरी और डील लेटर में हस्ताक्षर करके ली गई रकम को एफएसएल और हस्ताक्षर विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है और उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया जा सकता है। और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बिल्डरों को जेल भी जाना पड़ सकता है। क्योंकि कानून से कोई बच नहीं सकता।

निस्वार्थ सेवा का फल: पर्वतम्मा की मृत्यु पर एक बंदर का विलाप और मानवता का संदेश

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। हमारे यहाँ एक कहावत है, "अच्छे कर्म करो और उन्हें समुद्र में बहा दो।" इसका अर्थ यह है कि यदि आप किसी जानवर, पक्षी या गरीब इंसान की मदद बिना किसी अहंकार या प्रतिफल की अपेक्षा के करते हैं, तो वही सच्ची परोपकारिता है। इसे निस्वार्थ सेवा कहते हैं, और उस निस्वार्थ सेवा के फल स्वरूप, पत्थर दिल इंसान भी विनम्र हो जाता है और आपसे घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए विवश हो जाता है। चाहे वह व्यक्ति कितना भी खूंखार जंगली जानवर क्यों न हो, क्यों नहीं? यहां एक ऐसी ही कहानी है, जिसमें एक महिला, जो हर दिन एक बंदर को खाना खिलाती थी, की मृत्यु

हो गई और बंदर के विलाप ने भालाभला की आंखों में आंसू ला दिए। कर्नाटक के रामनगर जिले के रायरा डोट्टी गांव में ऐसी ही एक घटना घटी, जिसने गांव वालों को भावुक कर दिया। 85 वर्षीय पार्वतीम्मा का वृद्धावस्था के कारण एक छोटी बीमारी से निधन हो गया। पार्वतीम्मा ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बंदरों को समर्पित कर दिया था। वह हर दिन अपने घर आने वाले बंदरों को पुकारती, खाना खिलाती और सहलाती थीं। उनके आसपास के लोग बंदरों को मुसीबत मानते थे। लेकिन पार्वतीम्मा के लिए, उनके आंगन में आने वाले बंदर उनके अपने ही थे। जब पार्वतीम्मा के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए प्रांगण में रखा गया, तो भीड़ को चीरते हुए एक बंदर वहाँ आया। उसने पार्थिव शरीर के चेहरे पर पड़ा कपड़ा हटाया और कुछ क्षण चुपचाप वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद वह पार्थिव शरीर के पास गया और उसके चेहरे को सहलाया। फिर उसने पार्वतीम्मा की छाती को गले लगाया और रोने लगा। बंदर ने कितनी देर तक अपनी आँखें बंद रखीं और पार्वतीम्मा की छाती, मुँह और माथे को ऐसे चूमता रहा जैसे उन्हें चूम रहा हो। ऐसा लगता है कि वह अपने अंतिम सहारे के बिछड़ने का शोक मना रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यह दृश्य देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। जब बंदर के इस भावुक दृश्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि समझदार लोगों की आँखें भी नम हो गईं। यहां यह बताना जरूरी है कि सूरत के एक अस्पताल की नर्स ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें एक बुजुर्ग मरीज, जिनका बिस्तर खिड़की के पास था, की छाती पर रोजाना एक कबूतर आकर बैठता था। 15 मिनट बाद, मरीज अपना हाथ घुमाता और कबूतर उड़ जाता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि मरीज रोजाना कबूतरों को दाना खिलाता था।

दवा के बिल पर लोकतंत्र की पुकार: राजकोट में वोटिंग जागरूकता का अनोखा प्रयोग

राजकोट। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जागरूक मतदाता सबसे बड़ी ताकत होते हैं, और इसी सोच को जमीनी स्तर पर उतारते हुए राजकोट जिला प्रशासन ने एक अभिनव और प्रभावशाली पहल शुरू की है। अब यहां मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने वाले लोगों को मिलने वाले बिल केवल दवाओं का हिसाब नहीं बताएंगे, बल्कि उन्हें उनके अधिकार और जिम्मेदारी—मतदान—की याद भी दिलाएंगे।

स्थानीय निकाय चुनाव 2026 को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई इस पहल के तहत दवा के हर बिल पर एक विशेष संदेश अंकित किया जा रहा है—"मेरा वोट मेरा अधिकार है – चलो वोट करें।" यह छोटा सा संदेश लोगों को यह एहसास दिलाने की कोशिश है कि लोकतंत्र में उनकी भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है।

यह पहल इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि यह सीधे लोगों के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ती है। आमतौर पर दवा खरीदते समय हर व्यक्ति बिल जरूर देखता है—चाहे वह कीमत जांचने के लिए हो या दवा की जानकारी के लिए। ऐसे में उसी बिल पर मतदान का संदेश दिखाई देना लोगों के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। यह एक ऐसा माध्यम है जो बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के हजारों लोगों तक रोजाना पहुंच रहा है।

इस अभियान को जिला प्रशासन की 'SWAP' (Systematic Voters' Awareness Program) गतिविधि के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक चुनाव की तारीख और मतदान के महत्व को पहुंचाना है। बिल पर न केवल प्रेरक संदेश दिया जा रहा है, बल्कि 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव की तारीख भी स्पष्ट रूप से अंकित की जा रही है, ताकि लोग इसे भूल न सकें। इस पहल में तालुका और जिला पंचायत, नगर निगम तथा गोंडल नगरपालिका के सामान्य और उपचुनाव से जुड़ी जानकारी भी शामिल की गई है। यानी यह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक संपूर्ण सूचना माध्यम बन गया है, जो लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ उन्हें चुनाव प्रक्रिया से जोड़ने का काम कर रहा है। इस कार्यक्रम की नोडल अधिकारी जिज्ञाशाबेन गढ़वी के अनुसार, यह पहल प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय संस्थाओं के संयुक्त प्रयास का परिणाम है।

नवनिर्मित स्टाफ क्वार्टर एवं एकीकृत नियंत्रण कार्यालय का उद्घाटन

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में दिनांक 18 अप्रैल 2026 (शनिवार) को मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के करकमलों द्वारा नवनिर्मित स्टाफ क्वार्टर (टाइप-II) तथा डीआरएम कार्यालय, भावनगर परा में स्थापित नवीन एकीकृत नियंत्रण कार्यालय (इंटीग्रेटेड कंट्रोल ऑफिस) का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री ऋत्विक शर्मा एवं मंडल इंजीनियर (समन्वय) श्री डी. एस. यादव की गरिमामयी उपस्थिति रही।

स्टाफ क्वार्टर का उद्घाटन

मंडल में रेल कर्मचारियों के बेहतर आवासीय सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में नवनिर्मित टाइप-II स्टाफ क्वार्टर का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आवासीय परियोजना कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार एवं कार्य-जीवन संतुलन को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगी।

एकीकृत नियंत्रण कार्यालय (Integrated Control Office) डीआरएम कार्यालय, भावनगर परा में स्थापित आधुनिक एकीकृत नियंत्रण कार्यालय का उद्घाटन भी इसी अवसर पर किया गया। यह सुविधा मंडल में समन्वय, सुरक्षा, संरक्षा तथा परिचालन दक्षता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

नव विकसित नियंत्रण कार्यालय को आधुनिक, एर्गोनोमिक एवं तकनीक-अनुकूल कार्यस्थल के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें मॉड्यूलर फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर तथा एयर कंडीशनिंग की समुचित व्यवस्था की गई है, जिससे 24×7 कार्यरत कर्मचारियों के लिए आरामदायक एवं कुशल कार्य वातावरण सुनिश्चित होगा।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस एकीकृत व्यवस्था के अंतर्गत मंडल के विभिन्न प्रमुख नियंत्रणों को एक ही छत के नीचे लाकर एक समन्वित कमांड एवं नियंत्रण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित नियंत्रण शामिल हैं:

ट्रेन ऑपरेशन कंट्रोल: यात्री एवं मालगाड़ियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग एवं संचालन

आरपीएफ (सुरक्षा) कंट्रोल: यात्रियों एवं रेलवे संपत्ति की सुरक्षा हेतु 24×7 निगरानी

पावर एवं कैरिज कंट्रोल: लोकोमोटिव प्रदर्शन एवं कोच रखरखाव की निगरानी

इंजीनियरिंग कंट्रोल: पटरियों के रखरखाव एवं अवसंरचना कार्यों का समन्वय

इलेक्ट्रिकल कंट्रोल: स्टेशन लाइटिंग एवं अन्य विद्युत आपूर्ति का प्रबंधन

सिग्नल एवं दूरसंचार कंट्रोल: सिग्नलिंग एवं संचार प्रणाली की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना

कमर्शियल कंट्रोल: यात्री सुविधाओं, टिकट जांच एवं राजस्व की निगरानी

डिजास्टर मैनेजमेंट कक्ष: आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित समन्वय हेतु समर्पित सुविधा

यह अत्याधुनिक एकीकृत नियंत्रण प्रणाली त्वरित निर्णय लेने, बेहतर समन्वय स्थापित करने, प्रभावी आपदा प्रबंधन तथा ट्रेन संचालन की कुशल निगरानी सुनिश्चित करेगी।

भावनगर मंडल का रेल वॉर रूम (Rail War Room) मंडल कार्यालय में स्थापित 24x7 सक्रिय अत्याधुनिक नियंत्रण केंद्र है, जो ट्रेनों की आवाजाही, यात्री शिकायतों और सुरक्षा की रियल-टाइम निगरानी करता है। इसका उद्देश्य यात्रियों की परेशानियों (जैसे- गंदगी, खाना, सुरक्षा) को तुरंत दूर करना और परिचालन संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना। यह केंद्र 24x7 काम करता है, जिसमें कर्मचारी रोटेशन में कंप्यूटर टर्मिनलों पर बैठकर ट्रेनों की लाइव मॉनिटरिंग करते हैं। रेल वॉर रूम को सीधे सोशल मीडिया, रेल मदद और 139 हेल्पलाइन से जोड़ा गया है, ताकि शिकायतों को त्वरित प्रतिक्रिया मिले। ट्रेन दुर्घटना या किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में, यह कक्ष वरिष्ठ अधिकारियों को त्वरित निर्णय लेने में मदद करता है। यह प्रणाली भीड़भाड़ वाले त्योहारों के समय विशेष रूप से प्रभावी होती है, जहां यह रीयल-टाइम में भीड़ नियंत्रण (Crowd Control) का काम करती है।

मंडल की प्रतिबद्धता

यह पहल भावनगर मंडल की डिजिटल परिवर्तन, सुरक्षा, संरक्षा, विश्वसनीयता एवं यात्री सुविधाओं के सतत उन्नयन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। साथ ही, यह आधुनिक, स्मार्ट एवं यात्री-केंद्रित रेलवे प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

पश्चिम रेलवे द्वारा साबरमती-दुर्गापुर के बीच समर स्पेशल ट्रेन का संचालन

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की मांग एवं भीड़ को ध्यान में रखते हुए साबरमती–दुर्गापुर–साबरमती समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। इसका विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 09421/09422 साबरमती–दुर्गापुर–साबरमती स्पेशल (विशेष किराया पर)

ट्रेन संख्या 09421 (साबरमती–दुर्गापुर स्पेशल) दिनांक 21 एवं 26 अप्रैल, 2026 को साबरमती से 10:35 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन 01:00 बजे दुर्गापुर पहुंचेगी।

ट्रेन संख्या 09422 (दुर्गापुर–साबरमती स्पेशल) दिनांक 23 एवं 28 अप्रैल, 2026 को 04:00 बजे दुर्गापुर से प्रस्थान करेगी तथा दूसरे दिन 19:30 बजे साबरमती पहुंचेगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन महेसाणा, पालनपुर, आबू रोड, अजमेर, जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, ईदगाह आगरा, टूंडला, गोविंदपुरी, सूबेदारगंज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सासाराम, गया, कोडरमा, धनबाद, आसनसोल एवं अण्डाल स्टेशनों पर रुकेगी।

ट्रेन सं. 09421 (साबरमती–दुर्गापुर स्पेशल) के लिए आरक्षण की बुकिंग 20 अप्रैल, 2026 से सभी PRS काउंटर्स एवं IRCTC वेबसाईट पर उपलब्ध होगी।

इस ट्रेन में 3-टियर एसी एवं 3-टियर एसी एकोनोमी श्रेणी के कोच रहेंगे।

भावनगर टर्मिनस - हावड़ा जंक्शन के बीच 20 अप्रैल और 27 अप्रैल को चलेगी "समर स्पेशल ट्रेन"

यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि में अतिरिक्त यात्री सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ट्रेन ऑन डिमांड (TOD) के अंतर्गत विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन विशेष किराया (Special Fare) पर संचालित की जाएगी।

यात्रियों की सुविधा हेतु पश्चिम रेलवे द्वारा भावनगर टर्मिनस और हावड़ा जंक्शन के बीच "समर स्पेशल ट्रेन" संचालित की जाएगी। यह सेवा भावनगर टर्मिनस से 20 अप्रैल 2026 और 27 अप्रैल 2026 को संचालित की जाएगी। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार ट्रेनों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है—

ट्रेन नंबर 09531 भावनगर टर्मिनस – हावड़ा जंक्शन समर स्पेशल 20 अप्रैल, 2026 और 27 अप्रैल, 2026 को संचालित होगी। यह ट्रेन भावनगर टर्मिनस से सोमवार को शाम 17.45 बजे प्रस्थान कर बुधवार को रात्रि 21.40 बजे हावड़ा जंक्शन पहुंचेगी।

इसी प्रकार वापसी में ट्रेन संख्या 09532 हावड़ा जंक्शन– भावनगर टर्मिनस समर स्पेशल 23 अप्रैल, 2026 और 30 अप्रैल, 2026 को संचालित होगी। यह ट्रेन हावड़ा जंक्शन से गुरूवार को सुबह 10.50 बजे प्रस्थान कर शनिवार को सुबह 06.30 बजे भावनगर टर्मिनस पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में सोनगढ़, धोला, बोटाद, सुरेन्द्रनगर गेट, विरमगाम, महेसाना, पालनपुर जं., आबूरोड, अजमेर जंक्शन, जयपुर जंक्शन, बांदीकुई जंक्शन, भरतपुर जंक्शन, अछनेरा जंक्शन, ईदगाह जंक्शन, टुंडला जंक्शन, गोविंदपुरी, प्रयागराज जंक्शन, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, सासाराम, गया जंक्शन, कोडरमा, धनबाद जंक्शन, आसनसोल जंक्शन, दुर्गापुर, बर्धमान एवं बैण्डेल जं. स्टेशनों पर ठहरेगी। ट्रेन में स्लीपर तथा जनरल श्रेणी के कोच उपलब्ध रहेंगे।

ट्रेन नंबर 09531 के लिए टिकटों की बुकिंग यात्री आरक्षण केंद्रों एवं आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द हीं प्रारंभ होगी। यात्रीगण ट्रेन के समय, ठहराव एवं संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर अवलोकन कर सकते हैं।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने यात्रियों से अपील की है कि वे इस विशेष ट्रेन सेवा का अधिकतम लाभ उठाकर अपनी यात्रा को सुगम एवं सुविधाजनक बनाएं।

20 अप्रैल को कुछ ट्रेनें साबरमती स्टेशन पर नहीं रुकेगी

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल के साबरमती स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्य के संबंध में इंजीनियरिंग कार्य हेतु 20 अप्रैल 2026 को ब्लॉक लिया गया है। जिसके कारण कुछ ट्रेनों का ठहराव साबरमती (जेल साइड) स्टेशन पर स्थगित किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

20 अप्रैल को साबरमती स्टेशन (जेल साइड) पर ठहराव नहीं करने वाली ट्रेनें:

- ट्रेन संख्या 19016 पोरबंदर-दादर सौराष्ट्र एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 22926 ओखा-अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 22960 जामनगर-वडोदरा इंटरसिटी एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 69186 विरमगाम-अहमदाबाद मेमू

यात्रियों से अनुरोध है कि उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखते हुए यात्रा करें। ट्रेन संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया https://enquiry.indianrail.gov.in वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अहमदाबाद मंडल की ऐतिहासिक उपलब्धि : जम्मू–कश्मीर के लिए पहली बार भेजी गई दूध उत्पादों की कार्गो रेक

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने माल परिवहन के क्षेत्र में एक नई ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए जम्मू-कश्मीर के लिए दुग्ध उत्पादों की अपनी पहली कार्गो रेक सफलतापूर्वक रवाना की है।

यह विशेष खेप गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (अमूल) के लिए लिंच (LCH) स्टेशन से लोड की गई है। इस रेक में कुल 20 BCN वैगन शामिल हैं, जिन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है—10 वैगन बारी ब्राह्मण (BBMN) तथा शेष 10 वैगन उत्तर रेलवे के जम्मू-तवी मंडल के अनंतनाग (ANT) स्टेशन के लिए भेजे गए हैं।

इस परिवहन से रेलवे को 24.62 लाख का माल भाड़ा राजस्व प्राप्त हुआ है। यह पहल न केवल डेयरी उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि देश के दूरस्थ क्षेत्रों तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व अक्टूबर 2025 में कश्मीर घाटी में माल परिवहन के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की गई थी, जब 1,350 टन औद्योगिक नमक की पहली रेल खेप गुजरात के अहमदाबाद मंडल के खाराघोड़ा (KOD) स्टेशन से अनंतनाग (ANT) स्टेशन तक सफलतापूर्वक पहुंचाई गई थी।

नमक और दुग्ध उत्पादों की इन सफल खेपों के माध्यम से अहमदाबाद मंडल ने जम्मू-कश्मीर के साथ अपने व्यापारिक एवं आर्थिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ किया है। यह पहल गुजरात के डेयरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों को कश्मीर घाटी के बाजारों से सीधे जोड़ने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगी।